04 - बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले होने के मायने

05 - ज्ञान, मनोरंजन और भ्रम के बीच टीवी

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 21 नवम्बर, 2025

06 - मृत व्यक्ति के खाते से भी ट्रांजैक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों...

07 - स्वास्थ्य सेवाएं जनता का अधिकार हैं और किसी भी स्थिति में...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 81, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

बिहार के नतीजे चार राज्यों में बीजेपी की संभावनाओं के बारे में क्या बताते हैं?

डीके सिंह

कुछ दिन पहले, भाजपा सांसद अनिल बलूनी के इगास उत्सव में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से कहा था कि एनडीए 160 सीटें जीतेगा। आखिर में एनडीए को 202 सीटें मिलीं। यानी उन्हें भी हल्की लहर की उम्मीद थी, सुनामी की नहीं। ऐसा नहीं था कि इस चुनाव में जाति फैक्टर या पहचान की राजनीति खत्म हो गई हो और पत्रकार इसे देख नहीं पाए हों। अब सवाल यह है कि बिहार से मिली सीखों को कैसे उन चार राज्यों–पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पर लागू करें, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे? फिलहाल इसे बीजेपी के नज़रिए से देखें। बिहार का चुनाव परिणाम भारी एंटी-इनकंबेंसी के बावजूद मिली इस स्तर की जीत के लिहाज़ से अकेला नहीं है। मध्य प्रदेश (2023), हरियाणा (2024) और महाराष्ट्र (2024) के नतीजे देखिए–मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें, हरियाणा में 90 में से 48 और महाराष्ट्र में बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 132 (एनडीए का 232) में से 288। दिल्ली में भी बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतीं, हालांकि, वहां श्रेय का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल को भी जाता है।

इस सफलता के नुस्खे का पहला और शायद सबसे असरदार तत्व है–चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को नकद राशि का ट्रांसफर : मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, महाराष्ट्र में माझी लाडकि बहिण योजना, बिहार में महिला रोजगार योजना। बीजेपी ने 2022 में गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी–182 में से 156 सीटें–वह भी बिना किसी फ्रीबी राजनीति का सहारा लिए। गुजरात जीत के बाद अमित शाह ने कहा था कि वोटरों ने फ्रीबीज वादे करने वालों को खारिज कर दिया। यह तब हुआ जब कांग्रेस ने 2023 में कर्नाटक में बीजेपी सरकार को अपनी पांच 'गारंटियों' या फ्रीबीज़ के दम पर हटा दिया। उसके बाद मोदी-शाह ने तय किया कि विपक्ष को उन्हीं के हथियार से हराया जाए। अब कैश ट्रांसफर, सहायता राशि और फ्रीबीज़ चुनावों में बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी बन गए हैं। अगर फ्रीबीज़ से वोटर 'खरीदे' जा सकते थे, तो यह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों के लिए क्यों काम नहीं आया? क्योंकि राहुल गांधी वाली कांग्रेस में भरोसे और विश्वसनीयता का भारी संकट है। हिमाचल प्रदेश (2022) और कर्नाटक (2023) में कांग्रेस की फ्रीबी योजनाओं पर लोग सकारात्मक थे, क्योंकि तब तक पीएम मोदी 'रेवड़ी' बांटने के खिलाफ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने भी यही शुरू कर दिया, तो वोटरों का कांग्रेस पर अविश्वास वापस उभर आया।

तो फ्रीबीज़ को बीजेपी की चुनावी सफलता की रेसिपी का पहला तत्व मानिए। दूसरा है–बड़े सामाजिक गठबंधन बनाना। देखें कि बीजेपी कैसे हर राज्य में जाति और समुदाय आधारित छोटी पार्टियों को साथ लाती है। पीएम मोदी की अपील, आरएसएस का ढांचा, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, समर्पित कैडर और मजबूत संगठन–ये सब तो स्थायी कारक हैं ही।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने विजय भाषण में कहा, 'गंगा नदी बिहार से बंगाल की तरफ बहती है और बिहार की जीत, गंगा की तरह, बंगाल में हमारी जीत का रास्ता बना रही है।' उन्होंने यह अनदेखा कर दिया कि गंगा बिहार से पश्चिम बंगाल झारखंड होते हुए जाती है। लोकसभा चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अगर कहीं नुकसान हुआ है, तो वह सिर्फ झारखंड में हुआ–वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के हेमंत सोरेन की वजह से। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के लिए अब भी कठिन चुनौती बनी हुई हैं। उसने ओडिशा में बीजेडी को हरा दिया, लेकिन बाकी जगह मुकाबला उतना आसान नहीं है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सिर्फ जम्मू क्षेत्र में ही अपनी पकड़ बनाए रख सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम-बहुल कश्मीर घाटी में बीजेपी को बाहर रखा। तेजस्वी की आरजेडी भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस की तरह बना दिया है–जमा हुआ वोट बैंक और वही पुरानी, थकी हुई राजनीति।

अब देखिए, चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी के सामने कैसी चुनौती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उभरने के बाद से लगातार उन्हें रोकती आ रही हैं। बंगाल में बीजेपी ने भी एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश की–राजबंशी और मतुआ समुदायों को साधने की, जो राज्य के दलितों का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा हैं, और दलित जनसंख्या कुल आबादी का 23.5 प्रतिशत है। बीजेपी ने 5.8 प्रतिशत की जनसंख्या वाले आदिवासियों में भी पैठ बनाई। इन सामाजिक गठबंधनों के साथ पीएम मोदी की अपील, आरएसएस का ज़मीनी नेटवर्क और ध्रुवीकरण की रणनीति ने 2019 में बीजेपी के लिए चमत्कार किया– 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतीं। बनर्जी ने जवाब में इन्हीं समुदायों तक और ज्यादा पहुंच बनानी शुरू की, उदाहरण के लिए इनके लिए योजनाएं शुरू करना और राज्य पुलिस में नारायणी बटालियन बनाना, जिसका नाम कोच राजा, नर नारायण के नाम पर है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोच-राजबंशी बहुल कूचबिहार में टीएमसी से हार गई, और उत्तर बंगाल की कई सीटों में उसके जीत के अंतर भी घट गए। ममता बनर्जी ने इस साल की शुरुआत में लोकप्रिय 'लक्ष्मी भंडार' योजना में रकम बढ़ाकर आम वर्ग के लिए 500 से 1000 रुपये और दलित-आदिवासियों के लिए 1000 से 1200 रुपये कर दी। 2019 के बाद से उनकी सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दे रही है। ममता बीजेपी से एक कदम आगे रहने की कोशिश करती हैं।

तमिलनाडु में बीजेपी सिर्फ मोदी की अपील और हिंदुत्व पर नहीं टिक रही। कभी ब्राह्मण-हिंदी पार्टी समझी जाने वाली बीजेपी ने यहां पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया है। इन सामाजिक गठबंधनों को मजबूत सपोर्ट ब्लॉक बनाना बीजेपी के लिए अब भी जारी प्रक्रिया है। अभी उसे एआईएडीएमके की 'सवारी' करनी होगी–जो खुद अंदरूनी लड़ाइयों और करिश्माई नेता की कमी से जूझ रही है। विजय का राजनीति में आना विपक्षी वोटों को और बांट सकता है। केरल में बीजेपी सामाजिक गठबंधन बनाने और नायर व एझावा समुदायों में पैठ बनाने में लगी है, लेकिन यह रास्ता भी लंबा है–क्योंकि राज्य में 46त्न अल्पसंख्यक हैं। बिहार के नतीजे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को खुश करेंगे। न सिर्फ इसलिए कि उनकी ध्रुवीकरण वाली राजनीति एक ऐसे राज्य में असरदार रही है जहां अवैध प्रवासियों का मुद्दा संवेदनशील है। सरमा का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

दरिया हो या पहाड़ हो
टकराना चाहिए
जब तक न साँस टूटे
जिए जाना चाहिए
यूँ तो क़दम क़दम पे
है दीवार सामने
कोई न हो तो ख़ुद से
उलझ जाना चाहिए
झुकती हुई नज़र हो कि
सिमटा हुआ बदन
हर रस-भरी घटा को
बरस जाना चाहिए
चौराहे बाग़ बिल्डिंगें
सब शहर तो नहीं
कुछ ऐसे वैसे लोगों से
याराना चाहिए
अपनी तलाश अपनी
नज़र अपना तजरबा
रस्ता हो चाहे साफ़
भटक जाना चाहिए
चुप चुप मकान रास्ते
गुम-सुम निढाल वक्त
इस शहर के लिए कोई
दीवाना चाहिए
बिजली का क़ुमक़ुमा न
हो काला धुआँ तो हो
ये भी अगर नहीं हो तो
बुझ जाना चाहिए।

– निदा फ़ाज़ली

बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें

● सुप्रीम कोर्ट बोला-राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं

उच्चा न्यायालय ने कहा-डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी की तो दखल देंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों (विधेयकों) पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं। या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें या उन्हें प्रेसीडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोककर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-समयसीमा तय नहीं की जा सकती

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। न्यायपालिका भी ऐसे मामलों में अनुमानित स्वीकृति (डीम्ड असेंट) नहीं दे सकती। डीम्ड असेंट को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंजूरी के लिए गया है, और वे समय पर जवाब नहीं देते, तो कानून यह मान लेता है कि मंजूरी दे दी गई है। यानी, बिना बोले भी हां मान ली जाती है।

किसी भी गवर्नर के पास 3 संवैधानिक विकल्प हैं

मंजूरी, असेंबली को दोबारा विचार के लिए लौटाना और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना। गवर्नर 3 विकल्पों का इस्तेमाल करते समय अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियां उनके विवेक पर निर्भर हैं। किसी विधेयक पर फैसला लेते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं हैं। कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक, बिना किसी वजह के, या अनिश्चित देरी होने पर, कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही है। न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह रोक है, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई न करने की स्थिति में, संवैधानिक कोर्ट अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर सकता है। बेंच ने कहा– गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए न्यायिक रूप से समय सीमा तय करना सही नहीं है। राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता। राज्यपाल विधेयक को कानून बनाने के बीच सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की जगह इस मामले में चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली संविधान पीठ ने सुनवाई की। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रचूड़कर शामिल थे। सुनवाई 19 अगस्त से शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी उपस्थित थे।

खनन सुधार में जम्मू-नागालैंड से आगे उत्तराखंड

● दो महीनों में केंद्र ने दिए 200 करोड़

उत्तराखंड (एजेंसी)। उत्तराखंड खनन सुधारों के मामले में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को पछाड़कर आगे निकल चुका है। केंद्र सरकार ने ताजा मूल्यांकन में राज्य को इन दोनों सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। खनन क्षेत्र में लगातार सुधार, पारदर्शिता और बेहतर नीतियों ने उत्तराखंड को यह सफलता दिलाई है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष

2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जारी की है। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपए मिले थे।

यानी खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्य को अब तक कुल 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। राज्य ने माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम लागू किया, जिससे खनन और वाहनों की डिजिटल निगरानी संभव हुई। जीपी आधारित ट्रैकिंग, ई-ट्रांजिट पास और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ। खनन ब्लॉकों का जियो-टेक्निकल और फिजिकल सर्वे कराया गया, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

जहरीले केमिकल का सप्लायर शैलेष पांड्या गिरफ्तार

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला; 3 दिन की रिमांड पर भेजा

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ सिरप केस में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच टीम ने श्रीसन फार्मा को जहरीला डाय-एथलीन ग्लायकॉल (डीईजी) सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी शैलेष पांड्या को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पांड्या को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

सप्लाई चेन में सबसे अहम कड़ी निकला पांड्या- एसआईटी की जांच में सामने आया कि शैलेष पांड्या ही वह व्यक्ति था, जिसने उत्पादन कंपनी को कफ सिरप बनाने में उपयोग होने वाला रसायन उपलब्ध कराया था। प्राथमिक जांच में पाया गया कि सप्लाई किया गया DEG मानक गुणवत्ता का नहीं था और इसी जहरीले रसायन का इस्तेमाल कफ सिरप में हुआ, जो बच्चों की मौतों का कारण बना।

केस में अब तक 10 गिरफ्तारियां- पांड्या की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है। रसायन की खरीद, सप्लाई और स्टॉक से जुड़े कई दस्तावेज एसआईटी ने जब्त किए हैं।

अमर शहीद आशीष शर्मा की शहादत पर पूरे प्रदेश को गर्व : मुख्यमंत्री

परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता और छोटे भाई को बनाएंगे सब-इंस्पेक्टर

भोपाल (नप्र)। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को उनके गृह ग्राम बोहानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को शहीद आशीष शर्मा की अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे और शहीद की पार्थिक देह पर पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पार्थिक देह को कांधा भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आशीष शर्मा की शहादत पर प्रदेश को गर्व है।

परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद के परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। साथ ही, बोहानी गांव में शहीद आशीष शर्मा के नाम से एक पार्क और स्टेडियम भी विकसित किया जाएगा। इससे भावी पीढ़ियों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा मिलती रहे और उनकी स्मृति अक्षुण्ण बनी रहे।

शहीद के छोटे भाई को सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को शासकीय नियमों में शिथिलता बरतते हुए सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय परिवार को सम्बल देने और शहीद के अदम्य साहस को सदैव याद रखने और आमजन में राष्ट्रप्रेम के लिये प्रेरित करने के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।

शहीद के अंतिम संस्कार में मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री उदय प्रताप सिंह, सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री श्री जीतू पटवारी, पूर्व सांसद श्री कैलाश सोनी, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी, हॉक फोर्स के जवान और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे।

नीतिश कुमार 10वीं बार बने बिहार के सीएम

● 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, इनमें भाजपा के 14

● जदयू के 8, चिराग के 2 मंत्री, एक मुस्लिम चेहरा

पटना (एजेंसी)। नीतिश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जदयू से, लोजपा (आर) से 2 हम और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नगालैंड, ओडिशा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतिश कैबिनेट में इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह भी शामिल हैं। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेजप्रताप को मात दी थी। सीएम नीतिश कुमार के मंत्रिमंडल में भूमिहार जाति से दो लोगों को मंत्री बनाया गया है। इनमें बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा और जदयू से विजय चौधरी ने शपथ ली। राजपूत जाति से भी तीन मंत्री बनाए गए। इनमें जदयू से लेशी सिंह और भाजपा से संजय टाइगर और श्रेयशी सिंह ने शपथ ली। ब्राह्मण जाति से मंगल पांडेय ने शपथ लिया।

सीएम बनते ही ढेर सारी योजनाओं के देंगे हरी झंडी

बिहार में सत्ता का रण एक बार फिर नीतिश कुमार ने जीत लिया है। बिहार विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन ने आज गुरुवार को सरकार बना ली है। नीतिश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके फिर से मुख्यमंत्री बनते ही ढेर सारी योजनाओं को हरी झंडी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि नई योजनाओं का लाभ मिलने से पहले ही उनके मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन यानी कल 21 नवंबर शुक्रवार को बिहार की महिलाओं को फिर सौगात मिलने जा रही है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 21 नवंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

आतंकी मॉड्यूल में मुजम्मिल करता था रिक्रूटमेंट

● हर शख्स का काम तय था, शाहीन करती थी ब्रेनवॉश

फरीदाबाद (एजेंसी)। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। इस मॉड्यूल से जुड़े सभी प्रमुख डॉक्टरों की ड्यूटी तय थी। आतंक का नेटवर्क खड़ा करने में डॉ. मुजम्मिल शकील की अहम भूमिका रही है, जो लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद रिक्रूट करता था। नए लोगों को शामिल करने के बाद डॉ. शाहीन सईद और डॉ. उमर नबी उनकी आर्थिक मदद करते और ब्रेनवॉश करते थे। मुजम्मिल यह काम मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों के घर मदद के बहाने जाकर करता था। अस्पताल के जिन कर्मचारियों के नाम इस नेटवर्क में शामिल हैं, उनके परिवार वालों ने खुलासा किया है कि मुजम्मिल इलाज या किसी अन्य बहाने उनके घर आया था। यूं तो मुजम्मिल यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी वार्ड का सर्जन था, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भूमिका आतंकी मॉड्यूल में मदद करने वालों की टीम खड़ी करना था। वह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और अस्पताल में काम करने

वाले लोगों पर नजर रखता था। जरूरत पड़ने पर वह इलाज या अन्य तरीकों से लोगों से संपर्क करता और उनके घर की जानकारी जुटा लेता था। जांच एजेंसियों ने धौज गांव के शोएब को हिरासत में ले रखा है। शोएब को मई 2024 में यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय की नौकरी मिली थी, जिसमें उसे 8 हजार रुपए महीना पगार मिलती थी। शोएब के पिता शोहराब ने दैनिक भास्कर एप की टीम को बताया कि करीब एक साल पहले मेडिकल विंग में शोएब डॉ. मुजम्मिल के संपर्क में आया था। परिवार में किसी के बीमार होने पर शोएब उससे फोन पर बात करके दवाई पूछ लेता था। कुछ महीने पहले डॉ. मुजम्मिल उनके घर पर भी आया था। शोएब के जरिए आस-पड़ोस में कोई बीमार होता था तो वह आता था।

एसआईआर का डर, बंगाल में 'उलटा' पलायन!

● 500 बांग्लादेशी जीरो लाइन के पास फंसे, मची दहशत

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगे हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट (उत्तर 24 परगना) पर पिछले कुछ दिनों से असामान्य हलचल दिख रही है। सड़क किनारे झुंड बनाकर बैठे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के चेहरों पर भय साफ झलकता है। इनके पास पड़े बैग, कंबल और बक्से बताते हैं कि वे जल्दबाजी में अपना घर छोड़ कर आए हैं- केवल एक उद्देश्य के साथ कि उन्हें वापस बांग्लादेश लौटना है। संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अधिकारी इस उलट पलायन बता रहे हैं। यानी पहले ये लोग अवैध तरीकों से भारत में पलायन करके आए और अब भारत से भागने में लगे हैं।

अखबार से बात करते हुए अब्दुल मोमिन नाम के एक शख्स ने बताया कि वह पांच साल पहले सतखीरा जिले से भारत में दाखिल हुआ। उन्होंने कहा कि एक दलाल को पैसे देकर आए थे। हम हावड़ा के डोमजूड़ में रहते थे। जब एसआईआर शुरू हुआ तो डर लगने लगा। सुना कि बीएसएफ वापस भेज रही है, इसलिए पत्नी और दो बच्चों के साथ सुबह-सुबह यहां आ गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर नाटकीय घटना ने राजनीतिक विवाद को नई ऊंचाई दे दी है। लगभग 500 अवैध बांग्लादेशी नागरिक विशेष गहन संशोधन अभियान के डर से अपने देश लौटने की कोशिश में जीरो लाइन पर फंस गए हैं। ये लोग कोलकाता के उपनगरीय इलाकों में वर्षों से छिपकर रह रहे थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इन्हें भारत में वापस आने से रोक दिया, जबकि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन्हें बांग्लादेश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। यह घटना चुनाव आयोग के मतदाता सूची सफाई अभियान के बीच हुई है, जिसे विपक्षी दल भाजपा अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम बता रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है।

6100 महिलाओं ने साथ में किया डांस, हर साल मनेगा उत्सव

● 'घूमर' महोत्सव ने दिखाई राजस्थान की समृद्ध लोक-संस्कृति

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की शुरुआत, बनाया नया रिकार्ड

जयपुर (एजेंसी)। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की पहल पर पहली बार सातों संभागों में घूमर महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें 6,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर कर एशिया रिकॉर्ड बनाया। जयपुर में मुख्य कार्यक्रम में ट्रेडीशनल पहनावे में महिलाओं ने शानदार प्रस्तुति दी।

दीया कुमारी ने कहा कि घूमर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यह आयोजन हर साल होगा। उपमुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दीया कुमारी की पहल पर राजस्थान में पहली बार सातों संभाग मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग के इस भव्य आयोजन में करीब 6,000 महिलाओं ने एक ही समय पर घूमर डांस कर इतिहास रच दिया, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुए मुख्य समारोह में महिलाओं ने रंग-बिरंगी ट्रेडिशनल कपड़ों में घूमर की खूबसूरत प्रदर्शनी दिखाकर राजस्थान की समृद्ध लोक-संस्कृति को नई ऊर्जा से भर दिया। दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाया।

● घूमर को किया जाएगा सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल - डिप्टी सीएम दीया कुमारी खुद सांसद मंजू शर्मा और दूसरी प्रतिष्ठित महिलाओं के साथ मंच पर आईं और सबके साथ मिलकर घूमर नृत्य में भाग लिया। महोत्सव में घूमर की प्राचीन शैली को 'एक बार हो पिया जयपुर शहर पधार जो' गीत के जरिए खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर इस घूमर महोत्सव को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल कराने की तैयारी भी की जा रही है। महिलाओं को संबोधित करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि अब वो समय आ गया है, जब राजस्थान की लोक-संस्कृति, लोक कलाओं और समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।

दिल्ली की ठंड में गर्माएगी ग्लोबल जियो-पॉलिटिक्स

● भारत-रूस शिखर सम्मेलन पश्चिम के लिए है अलार्म?

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिसंबर में दिल्ली की सर्दी चरम पर होगी। ठिठुरन भरी ठंड के बीच ग्लोबल जियो-पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्म रहेगी। क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े नेता एक साथ नई दिल्ली में होंगे। दरअसल 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को लगता था कि वे भारत पर मॉस्को से दूरी बनाने का दबाव डालकर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके उलट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं और दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं कि यह साझेदारी कम नहीं, बल्कि और मजबूत हो रही है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर अभी से तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन का यह भारत दौरा किसी साधारण कूटनीतिक मुलाकात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाया और आरोप लगाया कि नई दिल्ली अप्रत्यक्ष रूप से रूस के युद्ध प्रयासों को फंडिंग कर रही है, तब भी भारत ने घुटने नहीं टेके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संप्रभु ऊर्जा विकल्पों का पुरजोर बचाव किया और पुतिन ने मोदी के इस अपमान स्वीकार न करने के रुख की तारीफ की। अब जब पुतिन दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो दांव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। दोनों देश एक ऐतिहासिक श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं, जिससे हजारों कुशल भारतीय कामगारों को रूस में कानूनी और सुगम तरीके से काम करने का रास्ता खुलेगा। रूस के लिए यह प्रतिबंधों से उपजी गंभीर श्रम कमी को पूरा करने का जरिया बनेगा, जबकि भारत के लिए प्रवास के नए अवसर पैदा होंगे। पश्चिमी देशों के लिए यह एक और झटका है कि उनके प्रतिबंध काम नहीं कर रहे।

सेवन हिल्स और अंकुर स्कूलों में बाल सप्ताह का समापन

भोपाल। बाल दिवस 14 नवंबर से विश्व बाल दिवस 20 नवंबर तक सेवन हिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू मार्केट, सेवन हिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ई-6 अरेरा कालोनी, अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल दयानन्द नगर और अंकुर स्कूल शिवाजीनगर में बाल सप्ताह का आयोजन चाइल्ड राइट्स ऑबजर्वेट्री के सहयोग से किया गया। इस वर्ष बाल सप्ताह की थीम 'सुरक्षा' रखा गया था जिसके अंतर्गत सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित यातायात, स्वयं की सुरक्षा, सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित भोजन-जल और सायबर सुरक्षा के कार्यक्रम अलग अलग दिन आयोजित हुए। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को चारों स्कूलों में बाल मेला आयोजित हुआ जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गयी पेंटिंग और ड्राइंग की प्रदर्शिनी लगाई गयीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, मेले में स्वस्थ्य पोषण आहार के स्टाल लगाए गए। बाल सप्ताह के दौरान चारों स्कूलों में चिकित्सक, शिक्षाविद, पुलिस अधिकारी, एडवोकेट आदि ने आकर बच्चों से बाल अधिकारों

के संबंध में संवाद किया। इन कार्यक्रमों में पालकों की उपस्थिति नियमित रूप से रही और वे भी बाल अधिकारों से अवगत हुए।

सेवन हिल्स स्कूल न्यू मार्केट में समापन के अवसर पर वरिष्ठ नृत्य गुरु और कथक नृत्यांगना श्रीमती अल्पना वाजपेयी मुख्य अथिति थीं। श्रीमती अल्पना वाजपेयी की शिष्याओं आध्या पाटील, शिवानी श्रीवास्तव, दिव्यांशी मेहरा ने समूह और श्रीमती चेतना विश्वकर्मा ने एकल कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। नृत्य कार्यक्रम में पालक- गण और छात्र- छात्राओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सेवन हिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ई-6 अरेरा कालोनी में शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य श्री संजय चौधरी और खेल अधिकारी श्री धुर्वे ने बाल मेले का शुभारंभ करते हुए प्रदर्शिनी का अवलोकन किया। अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजीनगर में रिटा. लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल चंद्रा और समाजसेवी श्री अनूप दुबे ने बाल मेले का शुभारंभ किया और ड्राइंग - पेंटिंग और विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल दयानन्द नगर में अर्पण संस्था की संचालक श्रीमती नीलिमा बागची मुख्य अतिथि थी।

एमपी के ज्यूडिशियल ऑफिसर 61 साल में होंगे रिटायर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्य सरकार तैयार है तो न्यायिक अधिकारियों को क्यों नहीं मिल रहा लाभ

भोपाल (नप्र)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 साल कर दी है। यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है, जिनमें न्यायिक सेवाओं में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग उठाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा...तो क्यों नहीं दे रहे लाभ- चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार इस निर्णय के लिए तैयार है, तो न्यायिक अधिकारियों को यह फायदा देने से इनकार क्यों किया जाए?

राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि न्यायिक अधिकारियों की उम्र अब तक 60 थी। हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष में रिटायर होते हैं, इसलिए जिला न्यायाधीशों की आयु

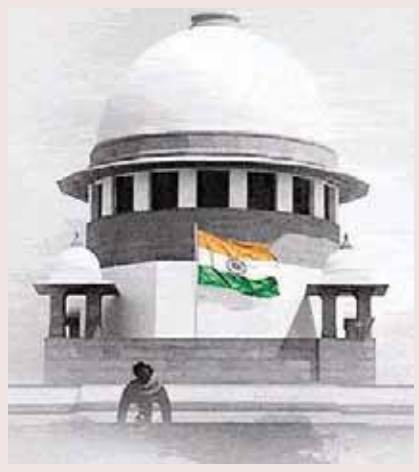

61 वर्ष करना तार्किक है। बेंच ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारी और राज्य के अन्य कर्मचारी एक ही पब्लिक एक्स चेकर से वेतन लेते हैं, इसलिए इस मामले में भेदभाव उचित नहीं।

तेलंगाना हाईकोर्ट का उदाहरण भी दिया- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट के समान निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो सकता है, तो मप्र में क्यों नहीं।

एमपी हाईकोर्ट ने किया विरोध- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन, जो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए इस विरोध को अभी स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई कानूनी बाधा नहीं

27 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार व हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था। 26 मई को भी चीफ जस्टिस गवई की बेंच ने कहा था कि सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है।

दोनों कर्मचारियों को एक ही खजाने से वेतन मिलता है

सीजेआई वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी और राज्य सरकार के बाकी कर्मचारी, दोनों का वेतन एक ही जगह यानी एक ही सरकारी खजाने से मिलता है। कोर्ट ने आगे राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल है। उच्च न्यायालय के जजों और जिला कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र में एक साल का डिफरेंट है।

उच्च न्यायालय के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और अब मध्यप्रदेश में जिला न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 61 साल हो जाएगी। बेंच ने इस याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद की तारीख तय की।

सभ्य समाज में यह किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं

● सुप्रीम कोर्ट बोला-इसका आविष्कार लोग कैसे करते हैं

एससी बोला-ऐसी प्रथाओं में कोर्ट को दखल देना पड़ेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिमों में तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम ने इस प्रथा की निंदा की। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आधुनिक और सभ्य समाज में ऐसी परंपरा स्वीकार की जा सकती है। इस भेदभावपूर्ण प्रथा का आविष्कार कैसे करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने वकील या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए तलाक का नोटिस भेजने पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा- यह वैध कैसे हो

सकता है। तलाक और तलाकनामा के नोटिस पर पति के साइन होने चाहिए। कोर्ट ने कहा- कोई तीसरा पक्ष महिला को उसके पति की ओर से तलाक कैसे सुना सकता है? क्या यह कानूनी है? क्या पति में इतना अहंकार है कि अपनी पत्नी को सीधे तलाक देने का प्रस्ताव भी नहीं रख सकता। समुदाय इस तरह की प्रथाओं को बढ़ावा कैसे दे रहा है? अगर समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं, तो कोर्ट को दखल देना होगा। इस्लाम में तलाक-ए-हसन तलाक देने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पति 3 महीने के दौरान हर महीने पत्नी को एक बार 'तलाक' कहता है।

● पति ने दूसरी शादी कर ली, पत्नी संघर्ष कर रही- बेनजीर के वकील रिजवान अहमद ने बताया कि 11 पन्नों के तलाकनामे में पति के साइन नहीं थे। ऐसे में यह कैसे माना जाए कि तलाकनामा पति ने ही भिजवाया था। ऐसे में अगर बेनजीर दोबारा शादी करती हैं, तो उन्हें एकसाथ दो पुरुषों से विवाहित माना जा सकता है। बेनजीर के वकील ने कहा कि जिस तरह से बेनजीर के पति ने तलाक-ए-हसन का नोटिस भेजा, उससे मेरी क्लाइंट यह साबित नहीं कर पाई कि उनका तलाक हो चुका है, जबकि उनके पति ने दोबारा शादी कर ली है। वह अपने जीवन में आगे भी बढ़ गए हैं। वहीं, बेनजीर अभी भी अपने पांच साल के बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

● इस्लाम इजाजत देता है, कोर्ट ने फटकारा- दूसरी तरफ, हिना के पूर्व पति का पक्ष रख रहे एडवोकेट एमआर शमशाद ने कहा कि मुसलमानों में यह प्रथा है कि पति अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस देने का अधिकार दे सकता है। इस पर कोर्ट ने वकील को फटकारते हुए कहा- यह कैसी बात है। आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। बेंच ने कहा- अब एक वकील तलाक देना शुरू कर देगा, अगर कोई पति पलट गया तो।

'मीटिंग कांड' के बाद अमित शाह से मिले शिंदे

कहा-माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में 'मीटिंग कांड' से हुए बवाल के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान शिंदे ने कहा है कि महायुति के कुछ नेता आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने शाह से यह भी कहा कि ऐसे व्यवधान महायुति गठबंधन की जीत में बाधा डाल सकते हैं और विपक्ष को फायदा पहुंचा सकते हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे की शाह से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही उनकी पार्टी शिवसेना के मंत्री राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। शिवसेना के मंत्री स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा द्वारा अपने पाले में लाने की कोशिशों का विरोध कर रहे।

एमपी में अभी भी शीतलहर का दौर जारी

भोपाल-इंदौर समेत 6 जिलों में अलर्ट; शाजापुर-राजगढ़ सबसे ठंडे

भोपाल (नप्र)। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से आधे मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा शाजापुर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर-उज्जैन समेत 15 शहरों में 10 डिग्री से नीचे रहा। भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में कोल्ड वेव यानी, शीतलहर चलेगी।

इस बार नवंबर के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। स्थिति यह है कि रात का पारा लगातार नीचे जा रहा है। इस वजह से भोपाल में नवंबर की सर्दी का पिछले 84 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। वहीं, इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी है। मौसम विभाग ने पूरे नवंबर में तेज ठंड का दौर बरकरार रहने का अनुमान जताया है। अगले दो दिन तक प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। फिर शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है।

10 डिग्री से नीचे चल रहा पारा

प्रदेश के 15 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल और इंदौर में पारे में फिर गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल में 7.8 डिग्री, इंदौर में 6.9 डिग्री, ग्वालियर में 10.7 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री और जबलपुर में 9.9 डिग्री रहा। इसी तरह पचमढ़ी में 6.6 डिग्री, नौगांव में 8 डिग्री, शिवपुरी में 9 डिग्री, खरगोन में 9.4 डिग्री, छिंदवाड़ा-मलाजखंड में 9.6 डिग्री और रीवा में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी शहरों में 10 से 13 डिग्री के बीच पारा टिका रहा।

इन जिलों में शीतलहर चलेगी

भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर और राजगढ़ में शीतलहर का अलर्ट है। इससे पहले भोपाल, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, सीहोर, खंडवा, खरगोन, शहडोल और जबलपुर में शीतलहर चली। शाजापुर का दिन कोल्ड डे दर्ज किया गया।

22 नवंबर को लो प्रेशर एरिया एक्टिव होगा

22 नवंबर से देश के दक्षिण-पूर्वी खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया (निम्न दबाव का क्षेत्र) एक्टिव हो रहा है। इससे पहले प्रदेश में अगले 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट है।

राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा तैयार किये गये मॉडल बने आकर्षण का केन्द्र

प्रदर्शनी का विषय सतत् भविष्य के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी इन दिनों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल में चल रही है। प्रदर्शनी में 31 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मिलकर विज्ञान पर केन्द्रित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किये हैं। यह मॉडल प्रदर्शनी में आने वाले बच्चों के बीच आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी का विषय सतत् भविष्य के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। बच्चों के लिये प्रदर्शनी अवलोकन प्रातः 9:30 से शाम 6:30 बजे तक रहता है।

प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के कुसुमकसा, बालोद के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों ने अभिनव प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है। यह प्रोटोटाइप नारियल के रेशे और परलाइट को उगाने के माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए एक आधुनिक मृदा-रहित कृषि तकनीक को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में छात्रा खुशी विश्वकर्मा और उनकी शिक्षक सुश्री सोनल गुप्ता बताती हैं कि पारंपरिक मृदा की आवश्यकता को इस तकनीक में पौधों को केवल पानी और आवश्यक पोषक तत्वों की सहायता से उगाया जाता है, जिसमें मृदा जनित रोगों को जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। यह विधि स्वच्छ, अधिक कुशल खेती और स्वास्थ्य वर्धक फसलों के लिये उपर्युक्त है। इस प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें पौधों को ऊर्ध्वाधर परतों पर उगाया जा सकता है, जिसमें कम भूमि में अधिक खाद उत्पादन संभव होता है, जो सीमित साधन या शहरी क्षेत्रों के लिये आदर्श समाधान है। इस प्रोटोटाइप में कृषि के साथ मछली पालन जैसी गतिविधियों का विस्तार भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय लालपानी छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिये भोजन प्रबंधन प्रणाली युक्त स्मार्ट चम्मच का प्रदर्शन किया है। इस साइंस मॉडल के बारे में विद्यार्थी दिव्यांशु सोनी गौरव और उनकी शिक्षक सुश्री नेहा शर्मा ने बताया कि इस मॉडल के माध्यम से भोजन की ताजगी का परीक्षण किया जा सकता है। तैयार किये गये प्रोटोटाइप में रियल टाइम में डिजिटल स्क्रीन पर परिणाम देखा जा सकता है। खाद्यान्न असुरक्षित पाये जाने पर उपकरण अलर्ट देता है। इस तरह के उपकरण से समाज में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा मिलेगा।

महाराष्ट्र राज्य के प्रगट विद्यामंदिर, रामगढ़ मालवन, सिंधु दुर्ग के छात्रों ने दर्भा घास से बनाया स्ट्रा पाइप को प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा तैयार किये गये उपकरण से प्लास्टिक स्ट्रा के विकल्प के रूप में घास से तैयार स्ट्रा का उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने सुप्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह की जयंती पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व प्रसिद्ध धावक, पद्मश्री सरदार मिल्खा सिंह की जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड में स्वर्ण पदक सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में ऐतिहासिक जीत से भारत को गौरवान्वित किया। उनका योगदान सदैव नई प्रतिभाओं को प्रेरित करता रहेगा।

राज्य गंगा समिति में 5 विशेषज्ञ सदस्य नामांकित

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में प्रवाहित गंगा की सहायक नदियों में जल का सतत् पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने एवं उनमें प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति मध्यप्रदेश में 5 विशेषज्ञ सदस्य नामांकित किये गये है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में डॉ अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को विषय विशेषज्ञ प्रदूषण अनुश्रवण, श्री कार्तिक सप्रे, समन्वयक, नर्मदा समग्र एनजीओ, भोपाल को नदी संरक्षण, प्रो. एस.पी. गौतम, पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को पर्यावरण संरक्षण, श्री सुनील चतुर्वेदी, संचालक, विभावरी संस्थान को जल संरक्षण और डॉ, जे.पी. शुक्ला, से.नि. प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सी.एस.आई.आर./एमपी को वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए नामांकित किया गया है। नामित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसर देय की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में पटना में आयोजित बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा उप मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों द्वारा मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग के समग्र उत्थान और 'विकसित बिहार' बनाने के संकल्प को नई गति व ऊर्जा देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ समर्पित रहेगी।

भोपाल के वोटर्स को खोजने बना पोर्टल, पुरानी सूची अपलोड

सभी विधानसभा की वोटर लिस्ट ; 2003 की सूची भी कर सकेंगे डाउनलोड

भोपाल (नप्र)। भोपाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) में 2003 के डाटा को खोजने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इसमें सभी विधानसभा की वोटर लिस्ट अपडेट है। वोटर पोर्टल पर जाकर सूची देख सकेंगे। इससे उन्हें एसआईआर फॉर्म भरने में आसानी होगी। इस पोर्टल के जरिए मतदाता मोहल्ले के नाम के आधार पर भी 2003 की मतदाता सूची खोज सकते हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल के मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को सरल एवं सुगम बनाने की सुविधा दी गई है। पोर्टल के माध्यम से मतदाता साल 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। वहीं, मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी विधानसभा की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। मतदान केंद्र बीएलओ की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे बड़ी परेशानी- बांटे गए फॉर्म वापस नहीं किए जा रहे

4 नवंबर से एसआईआर सर्वे शुरू हुआ है। अब तक की स्थिति में भोपाल जिले की स्थिति काफी खराब है। सात विधानसभा सीटों में 21 लाख 25 हजार 908 वोटर हैं। इनमें से 20.81 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन, वापस सिर्फ 1.57 लाख फॉर्म ही आए हैं। यह 7.37 प्रतिशत से भी कम हैं।

कार्रवाई का दौर भी जारी

एसआईआर में काम में देरी होने से कार्रवाई का दौर भी जारी है। कलेक्टर अब तक आधा दर्जन सुपरवाइजर-बीएलओ को निलंबित कर चुके हैं। वहीं, कई बीएलओ को नोटिस दिया गया है।

6वीं के छात्र को प्रिंसिपल ने पीटा

तबीयत खराब का कहकर पेरेंट्स को बुलाया, पिता बोले-चेहरे पर थप्पड़ के निशान-बेहोश हुआ, प्रिंसिपल बोलीं-आरोप बेबुनियाद

भोपाल (नप्र)। भोपाल में ईदगाह हिल्स स्थित गुरुनानक हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार दोपहर 6वीं कक्षा के छात्र 12 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है।

बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रिंसिपल सुरजीत कौर पर थप्पड़ मारने, गाली-गलौज करने, भविष्य खराब करने की धमकी देने और बच्चे को बेहोशी की हालत में छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों ने शाहजहांनाबाद थाने में प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

पिता का आरोप- चेहरे पर 10-15 थप्पड़ों के निशान- बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें मंगलवार दोपहर 2:08 बजे स्कूल से कॉल आया था कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। तुरंत स्कूल पहुंचें। जब स्कूल पहुंचे तो उनका बेटा अस्त-व्यस्त हालत में मिला। उसके चेहरे पर सूजन और थप्पड़ों के निशान थे और वह सांस लेने में तकलीफ के बाद अचानक बेहोश हो गया।

उसे आनन-फानन में चिरायु अस्पताल ले गए। जहां कुछ देर बाद उसे होश आया। इसके बाद बेटे ने बताया कि उसका सहपाठी से विवाद हो गया। उसकी क्लास टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गईं। जहां प्रिंसिपल सुरजीत कौर ने स्कूल कॉरिडोर में ही बच्चे को 10-15 थप्पड़ मारे।

पहले भी देती थीं धमकियां, टीसी देने की बात कहती थीं- पिता की शिकायत के अनुसार- प्रिंसिपल अक्सर मेरे बेटे को बुलाकर टीसी देने और साल खराब कर देने की धमकी देती थी। जब मैंने घटना को लेकर उनसे बात करनी चाही, तो उन्होंने मुझसे भी बदसलूकी की और स्कूल से जबर्दस्ती बाहर निकाल दिया।

जब मैंने शिकायत की तो उन्होंने बेटे के साथ उसी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को भी ऑनलाइन क्लास वाले व्हाट्सऐप ग्रुप से हटा दिया है।

मां से कहा- आपका बच्चा गुंडा बनेगा- बच्चे की मां ने बताया कि मंगलवार दोपहर 2:03 बजे प्रज्ञा सोनी मैम का कॉल आया कि प्रिंसिपल बुला रही हैं। जब हम पहुंचे तो बच्चा बेहोशी हालत में था। टीचर कह रहे थे कि दो बच्चों की लड़ाई हुई है। मैंने कहा दूसरे बच्चे के पेरेंट्स को बुलाइए, मैं उसका इलाज करवा दूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब हम बात कर रहे थे, तभी प्रिंसिपल बाहर आईं और बोलीं 'क्या गुंडा बनाओगी अपने बेटे को?' इसके बाद उन्होंने हमें जबरदस्ती स्कूल से बाहर कर दिया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि प्रिंसिपल मैम ने 7-10 थप्पड़ मारे।

हमने पुलिस से स्कूल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, तो जिम्मेदार कौन होता? हम प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं।

स्कूल प्रबंधन से संपर्क की कोशिश

इधर, घटना के बाद प्रिंसिपल सुरजीत कौर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। स्कूल प्रबंधन ने भी जांच या पक्ष को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं, शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी यूपीएस चौहान ने बताया कि हमारे पास इस तरह की शिकायत आई है। हम स्कूल के सीसीटीवी की जांच करवाएंगे। उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे।

प्रिंसिपल ने कहा-आरोप बेबुनियाद

स्कूल की प्रिंसिपल सुरजीत कौर ने छात्र के अभिभावकों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि दो छात्रों (जियान अली और देवराज साउद) के बीच का झगड़ा था, जिसे बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया। इस विवाद को स्कूल अनुशासन के तहत निपटाया जा रहा था। कौर के अनुसार 18 नवंबर को जियान स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी एक्टिवा पर सहपाठी देवराज साउद को लेकर गया था। आरोप है कि रास्ते में जियान ने देवराज को झटका देकर नीचे गिरा दिया। स्कूल को मामले की जानकारी मिलने पर दोनों बच्चों को बैठाकर समझाया गया और अनुशासन के नियम बताए गए।

बेटे के घर छोड़ने से दुखी मां ने जान दी

आखिरी मुलाकात में बेटे से कहा- बच्चों को घर छोड़ दो, मेरा घर सूना हो गया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बेटों के अलग होने से दुखी होकर महिला ने यह कदम उठाया है। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना बुधवार देर रात की है। गुरुवार दोपहर पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस के मुताबिक आशा बाई पति गेंदालाल यादव (47) प्रवेश नगर मालीखेड़ी गृहिणी थीं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। चारों बच्चों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटे मां-पिता से अलग अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बात से महिला दुखी थी।

छोटे बेटे ने 2 नवंबर को छोड़ दिया था घर- मृतका के छोटे बेटे संजय यादव ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर को मां और मेरे बीच विवाद हो गया था। वे कुछ सामान मंगा रही थीं, मैंने सामान लाने से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर मां ने फटकार लगाई, मैंने गुस्से में 2 नवंबर को घर छोड़ दिया। पत्नी बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगा।

दो दिन पहले आखिरी बार मां से की थी मुलाकात- बेटे के घर छोड़ने के बाद मां दुखी थी, दो दिन पहले उनसे मुलाकात करने गया था। तब मां ने बोला कि इतने बड़े घर में मन नहीं लगता, सूना हो गया है घर।

प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम पर हो निरंतर रिसर्च

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह की पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों से हुई चर्चा

भोपाल(नप्र)। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम पर निरंतर शोध करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में प्रदेश की संस्कृति, विरासत, आंचलिक विशेषताओं और जनजातीय गौरव जैसे विषयों को शामिल किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस प्रक्रिया से बच्चों को मध्यप्रदेश की विशेषताओं को समझने का मौका मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री बुधवार को मंत्रालय में पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में और वृद्धि के लिये शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण दिये जाने पर भी जोर दिया।

पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के सुझाव दिये। बैठक में तय हुआ कि स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये होने वाली बैठकों और कार्यशाला का निर्धारित कैलेण्डर तैयार किया जाये। बैठक में तय हुआ कि राज्य शिक्षा केन्द्र की लाइब्रेरी में अनुसंधान से जुड़ी पुस्तकों के संग्रह का विस्तार किया जाये। पाठ्यक्रम समिति की बैठकों में एनसीईआरटी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके भी सुझाव लिये जायें। बैठक में विभाग के टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के प्रस्तावित भवन के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में पाठ्यक्रम समिति के सदस्य डॉ. रविन्द्र कन्हारे, डॉ. अल्केश चतुर्वेदी, डॉ. भागीरथ कुमावत एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

31 दिसंबर 2020 तक झुग्गियों में रहने वालों को पट्टा

राजस्व और नगरीय विकास विभाग ने शुरू कराया सर्वे, फरवरी में बंटेंगे पट्टे

भोपाल (नप्र)। प्रदेश की शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत (गुरुवार) से सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग ने इस सर्वे के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सर्वे पूरा होने के बाद हर नगरीय निकाय यह सूची जारी करेगा कि तय तिथि तक कितने पात्र परिवार उनके क्षेत्र में निवासरत हैं। सर्वे के बाद प्रदेशभर के शहरी निकाय पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके आधार पर आगे पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कानून में किया संशोधन- सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधन के बाद पात्रता की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज रहने वाले आवासहीन परिवार पट्टाधिकार पाने के योग्य होंगे।

29 दिसंबर को कलेक्टर जारी करेंगे अंतिम सूची- प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर जारी करेंगे। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। हर जिले में सर्वे दल गठित किए जाएंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान आधार e-KYC आधारित समग्र ID अनिवार्य रहेगी।

4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच बंटेंगे पट्टे

नगरीय विकास आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के स्थायी एवं अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्थायी पट्टे लाल रंग में और अस्थायी पट्टे पीले रंग में दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग आवश्यक है, वहां समिति के निर्णय के अनुसार हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा।

धोखाधड़ी पर होगी कार्रवाई

स्थायी रूप से पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। राज्य शासन ने पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने और जन-जागरुकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। अवैध कब्जा, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर पट्टा प्राप्त करने जैसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ब्लैकलिस्ट तैयार की जाएगी।

स्कॉर्पियो से हो रही थी शराब तस्करी

पुलिस ने घेराबंदी कर अंग्रेजी शराब की 264 बोतलों सहित एक को पकड़ा

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कमला नगर पुलिस ने शबरी नगर इलाके से घेराबंदी कर स्कॉर्पियो सहित युवक को पकड़ा है। कार से 264 अंग्रेजी शराब की बाटलों सहित 36 बीयर की बोतल जब्त की गई। कार में चार युवक सवार थे। तीन पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार सहित शराब को जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

कमला नगर पुलिस ने बताया कि बुधवार की शाम सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी शबरी नगर में आई है। यहां पर रहने वाले लालू नाम के युवक के घर शराब आई है। जल्द ही उसे आसपास के इलाके में सप्लाई कर दिया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही तीन बदमाश वहां से भाग निकले जबकि एक युवक पुलिस गिरफ्त में आ गया।

3 लाख रुपए से अधिक कीमत की है शराब

पकड़े गए तस्कर की पहचान देव कुमार साहू निवासी राहुल नगर के रूप में हुई है। शराब की कीमत 3 लाख 14 हजार 448 रुपए बताई गई है। शराब सबरी नगर और आसपास की बस्तियों में सप्लाई करने के लिए मंगाई गई थी। पुलिस फरार आरोपियों लालू पटेल, राधे व अमित दुबे की तलाश में जुटी हुई है।

संपादकीय

मौत की तीर्थ यात्रा !

सउदी अरब के मक्का मदीना में उमरा के लिए गए 45 भारतीय जायरीनों की हादसे में दर्दनाक मौत वाकई दिल दहलाने वाली है। इस भयंकर हादसे में एक परिवार की तो तीनों पीढ़ियां खत्म हो गईं। केवल एक जायरीन शोएब बच पाया, जो ड्राइवर के पास बैठा था और समय रहते बस से कूद गया। 16 व 17 नवंबर की दरमियानी रात को हुई यह भीषण घटना कई लोगों की रूह कंपा गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय तीर्थ यात्रियों से भरी ये टूरिस्ट बस मक्का से मदीना जाते समय एक डीजल टैंकर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी बस जलकर राख हो गई। कई यात्री तो सोते में ही मर गए। मरने वाले में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर हैदराबाद के थे। वैसे कुल 54 लोग काबा ए शरीफ गए थे। इन लोगों ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए बुकिंग करवाई थी। सभी की वापसी 23 नवंबर को होनी थी। लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समय के मुताबिक रात लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे। उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ वो नौ लोग बच पाए, जो इस बस के बजाए कार से अलग जा रहे थे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर ने शोक व्यक्त किया है। इस बीच खबर है कि ज्यादातर मृतकों का अंतिम संस्कार सउदी अरब में किया जा जाएगा, क्योंकि सभी शव बुरी तरह जल गए हैं। तेलंगाना सरकार भी मृतकों के परिजनों की मदद कर रही है। जो परिजन सउदी अरब जाना चाहते हैं, उनके जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच इस हादसे की जांच की मांग और जिम्मेदारों को सजा की मांग भी परिजनों ने की है।

तेलंगाना सरकार के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से दो लोगों को सऊदी अरब भेजा जाएगा। वहां से शव भारत न लाकर सऊदी में ही धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया जाएगा। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन जारी की है। दूतावास ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे को नए सिरे से रेखांकित कर दिया है। मक्का और मदीना के बीच 450 किमी की दूरी है। यह कॉरीडोर हज और उमरा यात्रियों के लिए बेहद व्यस्त मार्ग माना जाता है। पूरे सऊदी अरब में इस रास्ते पर सड़क दुर्घटनाएं लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। यह हाई वे बेहद लंबा और रेतीला है। ऐसे में दुर्घटनाओं का जोखिम ज्यादा रहता है। रास्ता लंबा होने के कारण कई बार ड्राइवरों को भी नींद आने पर या आलस की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। सउदी अरब में बड़ी संख्या में तेल टैंकर गुजरते रहते हैं। इसलिए दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। भारतीय यात्री जिस उमरा के लिए सउदी अरब गए थे, उसे छोटी हज भी कहा जाता है। मुसलमानों की मान्यता है कि उमरा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। यह एक विशेष प्रकार की इबादत है, जिसे मुसलमान मक्का की पवित्र धरती पर जाकर अदा करते हैं। हालांकि उमरा हज की तरह फर्ज नहीं है। इसके तहत मुसलमान काबा शरीफ़ के पास कुछ निश्चित अरकान (रिवाज़) अदा करते हैं ताकि अल्लाह से माफी माँग सकें और रूहानी सुकून हासिल कर सकें। लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए यह मौत की यात्रा साबित हुई।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले होने के मायने

मुंबई जैसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली शहर में जहां हर सीट का महत्व है, वहां कांग्रेस का यह कदम पूरी राजनीति की रफ़्तार बदल सकता है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने यह मांग लंबे समय से उठाई थी कि पार्टी को बीएमसी जैसे विशाल मंच पर अपनी स्वयं की पहचान को सामने रखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन राजनीति ने कांग्रेस के लिए उम्मीद से कम परिणाम दिए, विशेषकर स्थानीय निकायों में। वर्ष 2017 के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस 31 सीटें लेकर तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि भाजपा 82 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं और यही कारण है कि कांग्रेस ने यह दांव खेला है। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने भी स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय इकाई ने जबरदस्त उत्साह से यह मांग की, और नेतृत्व ने उनका मत स्वीकार किया।

मुंबई की राजनीति में वह क्षण एक बार फिर सामने है, जब चुनाव सिर्फ एक स्थानीय निकाय का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की दिशा तय करने वाला माना जाता है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के दिसंबर-जनवरी में प्रस्तावित चुनावों को लेकर इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ, जब कांग्रेस ने महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में बने रहने के बावजूद अकेले चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया। यह फैसला जितना साहसिक दिखाई देता है, उतना ही यह संकेतों और संदेशों से भरा हुआ भी है। मुंबई जैसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली शहर में जहां हर सीट का महत्व है, वहां कांग्रेस का यह कदम पूरी राजनीति की रफ़्तार बदल सकता है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने यह मांग लंबे समय से उठाई थी कि पार्टी को बीएमसी जैसे विशाल मंच पर अपनी स्वयं की पहचान को सामने रखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन राजनीति ने कांग्रेस के लिए उम्मीद से कम परिणाम दिए, विशेषकर स्थानीय निकायों में। वर्ष 2017 के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस 31 सीटें लेकर तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि भाजपा 82 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं और यही कारण है कि कांग्रेस ने यह दांव खेला है। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने भी स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय इकाई ने जबरदस्त उत्साह से यह मांग की, और नेतृत्व ने उनका मत स्वीकार किया।

कांग्रेस का यह फैसला यूं ही नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरह गठबंधन का हिस्सा होकर कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिलीं, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में यह विश्वास पैदा हुआ कि स्वतंत्र लड़ाई अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अगर बिहार में अकेले लड़ती, तो वह कम से कम छह सीटें जीत सकती थी और उसका वोट प्रतिशत 12 से 14 प्रतिशत तक जा सकता था। लेकिन गठबंधन की मजबूरी ने कांग्रेस को वह अवसर नहीं दिया। कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं का उत्साह लगातार घट रहा था, और यही हताशा मुंबई में बड़े बदलाव का कारण बनी।मुंबई में कांग्रेस की स्थिति बिहार जितनी कमजोर नहीं है। यहां उसका परंपरागत वोट बैंक अभी भी काफी स्थिर है मुस्लिम वोटर लगभग 20-22 प्रतिशत, दलित 10-12 प्रतिशत और दक्षिण भारतीय समुदाय 8-10 प्रतिशत। यह तीनों समूह लंबे समय से कांग्रेस के कोर सपोर्टर रहे हैं। 2017 के चुनावों में जिन इलाकों में मुस्लिम बहुलता थी, वहां कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। आज भी मुंबई के दक्षिण और मध्य इलाकों तथा बांद्रा, अंधेरी, वर्ली जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन मजबूत माना जाता है। यही नहीं, पार्टी ने हाल के वर्षों में 50,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं और 1000 से अधिक टिकट आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संगठनात्मक ऊर्जा कांग्रेस को अकेले मैदान में उतरने का आत्मविश्वास देती है।

लेकिन कांग्रेस की इस चाल के पीछे सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति भी है। पार्टी को सबसे अधिक असहजता एमएनएस से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर थी। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हाल के महीनों में सहयोग के संकेत मिले मतदाता सूची में गड़बड़ियों के विरोध में हुई संयुक्त रैली इसका उदाहरण है तो कांग्रेस की चिंता गहराने लगी। राज ठाकरे की राजनीति पर कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है, खासकर 'मराठी मानूस' और प्रवासी-विरोधी अभियानों के कारण। वर्षा गायकवाड़ ने खुलकर कहा कि कांग्रेस कभी भी एमएनएस के साथ हाथ नहीं मिला सकती। यदि यह गठबंधन और मजबूत होता, तो न सिर्फ कांग्रेस को कम सीटें मिलतीं बल्कि उसका सेक्युलर वोट बैंक भी बिखर सकता था।उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले पर कहा कि हर दल को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और शिवसेना (यूबीटी) भी उसी तरह स्वतंत्र है। यह बयान दिखाता है कि एमवीए में सतही शांति के बावजूद अंदरूनी तनाव मौजूद है। कांग्रेस का मानना है कि यदि शिवसेना और एमएनएस मिलकर एक मजबूत मराठी फ्रंट बनाते हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 50-60 सीटें मिल सकती थीं, जबकि वह कम से कम 100 से अधिक सीटों पर लड़ने का दावा रखती है। कांग्रेस को यह भी आशंका है कि 'मराठी बनाम अन्य' की राजनीति में वह 'आउटसाइडर' बन जाएगी, जिससे उसके कोर वोटर्स दूर हो सकते हैं।

कांग्रेस की रणनीति में यह पहलू बेहद महत्वपूर्ण है कि अकेले लड़ने से उसे मुस्लिम और दक्षिण भारतीय वोटों का और अधिक एकजुट समर्थन मिल सकता है। एमएनएस के साथ शिवसेना की नजदीकी बढ़ने से मुस्लिम वोटर असहज हो सकते थे, और कांग्रेस इसी भावना का लाभ उठाकर स्वयं को एकमात्र मजबूत सेक्युलर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। यह कांग्रेस के लिए सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक स्थिति का भी बयान है। हालांकि इस फैसले से सबसे अधिक लाभ भाजपा को होने की आशंका है। भाजपा 2017 से अब तक बीएमसी में सबसे बड़ी ताकत रही है। यदि विपक्ष विभाजित होकर लड़ता है, तो भाजपा को बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि 'कब तक हम अपनी कीमत पर दूसरों का फायदा कराते रहेंगे?' पार्टी का मानना है कि एमवीए में उसकी भूमिका लगातार छोटी होती जा रही थी, और अब उसे अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन खुद करना होगा। मुंबई कांग्रेस के दो लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता, वर्षों से सड़कों पर सक्रिय पार्षद और मजबूत बूथ संरचना कांग्रेस के फैसले को वजन देती है। यह सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि अपना खोया हुआ राजनीतिक आधार पुनः हासिल करने का मौका है। मुंबई जैसे शहर में जहां हर समुदाय की राजनीतिक समझ अलग होती है, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह इस विविधता के भीतर अपनी जगह दोबारा बनाए। लेकिन अगर उसका वोट बैंक एकजुट हो गया, तो अकेले लड़ने का यह दांव उसके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

बहरहाल, यह फैसला कांग्रेस के लिए जोखिम और अवसर दोनों लेकर आया है। मुंबई की बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है देश की किसी भी नगरपालिका से बड़ा। यहां की राजनीति सिर्फ वार्डों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति तक असर डालती है। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया है। अगर यह दांव सफल रहा, तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस की वापसी की कहानी लिखी जाएगी; लेकिन अगर यह असफल हुआ, तो पार्टी को गहरे संगठनात्मक पुनर्विचार की जरूरत पड़ेगी। मुंबई की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है एक तरफ शिवसेना का अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष, दूसरी तरफ भाजपा की आक्रामक रणनीति, और अब कांग्रेस का अपने पैरों पर खड़े होने का ऐलान। यह चुनाव सिर्फ एक निकाय का नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान, उसकी राजनीति, और महाराष्ट्र की सत्ता संतुलन का भी फैसला करेगा। कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है, अब जनता की बारी है कि वह तय करे कि क्या यह आत्मविश्वास मुंबई में नई राजनीति का द्वार खोलेगा या फिर विपक्ष को और ज्यादा विभाजित कर देगा।

अभियान

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब की डॉ. आंबेडकर चेयर में चेयर प्रोफेसर हैं।

नशामुक्ति के खिलाफ पाँच वर्ष

भारत में नशामुक्ति के खिलाफ विगत पांच वर्षों से बड़ा अभियान भारत सरकार दवरा चलाया जा रहा है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की यह कोशिश है कि नशे से हमारे देश को मुक्ति मिले. सुखद यह है कि 8.09 करोड़ युवाओं और 5.49 करोड़ महिलाओं सहित 23.74 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक बनाया गया, ऐसा सरकारी दावा है. इस भागीरथ प्रयास में लगे 17 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों की भागीदारी कोई आम बात नहीं रही है। नशामुक्ति उपचार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 427 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गयी. 2020-21 में 1.86 लाख से 2024-25 में 7.98 लाख व्यक्तियों ने नशे से मुक्ति की या तो इच्छा व्यक्त की या तो वे खुद छोड़ने के लिए उचित तलाश किए हैं. इसमें से 5.72 लाख लोग ठीक हुए यानि उन्हें नशा से मुक्ति मिल गयी और सबसे अहम् बात यह है कि ये ठीक हुए व्यक्ति अब अभियान में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं. सरकार ने 20,000 से अधिक समर्पित मास्टर स्वयंसेवक तैयार किया और नशामुक्ति सुविधाएं 490 से बढ़कर 780 तक बढ़ाया इससे भी हमारे देश के लगभग 6 करोड़ लोग नशे से मुक्ति पा सके हैं. निःसंदेह आध्यात्मिक संगठनों के साथ सहयोग दिया और केवल आध्यात्मिक संगठनों के सहयोग का आकलन किया जाए तो उनके माध्यम से यह अभियान 3.37 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचा. देश की टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 व दूसरे उपक्रमों का भी इसमें बड़ा योगदान माना जा रहा है.

वस्तुतः यह जो सफलता भारत सरकार को मिली है इसके पीछे प्रधान एमएममंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प-संदेश काम किया है और साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार व सचिव अमित यादव के श्रेष्ठ प्रयास ने का यह परिणाम है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं. भारत में आज के समय में नशे की चंगुल में फंसी आबादी को निकाल पाना बहुत आसान नहीं है. सब प्रयास विफल हो जाते हैं जब एक बार नशे से निकला हुआ व्यक्ति दुबारा नशे में धुत मिलता है. लेकिन बार-बार कोशिश के बाद यह जो 6 करोड़ लोगों को नशे से निकालने में सफलता मिली है वह बड़े प्रयास के बाद संभव हो सका है. किसी भी राष्ट्र के लिए यह बड़ी दुखद खबर होती है कि उसकी नई पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है. इससे सभी सहमत होंगे की इस नशे की आगोश में आने वाली आबादी से केवल उसका नुकसान नहीं होता अपितु देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक नुकसान होता है. परिवार व समाज इससे परेशानी में आ जाते हैं. देश में स्ट्रेस के सबसे बड़े कारण ये नशेड़ी बन जाते हैं.

पंजाब में नशे की समस्या बहुत गंभीर है. ड्रग्स को लेकर पागल हुई युवा आबादी आज पंजाब सरकार को चुनौती दे रही है. देश को चुनौती दे रही है. जो दिमाग, हाथ-पांव देशहित में कार्य करते वे नशे में बेहोश हैं और किसी काम के नहीं हैं. ऐसे में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने जो अमृतसर में यह पांच वर्ष की सफलता के अपने आँकड़े के साथ अपनी उपस्थिति दी है, उससे बहुत बड़ा मैसेज पंजाब में गया है और जो नशे में धुत लोग यह सोचते थे कि वे नशा नहीं त्याग सकते वे यह अब समझेंगे कि लगभग छः करोड़ लोगों ने यदि नशामुक्ति पायी है तो वे भी पा सकते हैं.

अमृतसर में पांच वर्ष पूर्ण होने पर नशामुक्ति के खिलाफ जो भारी लोगों की संख्या एकत्रित हुई वह अद्भुत रही. नशा मुक्त भारत अभियान एक शक्तिशाली जन आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया है. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को समूल खत्म करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार का अपना मत और इसमें सम्मिलित हुए लोगों की यदि इच्छा बलवती बनी रही तो निश्चय ही देश में जड़ें जमा चुकी नशाखोरी की समस्या से भारत मुक्ति पा सकेगा. सभी जानते हैं कि यह अभियान उस कलंक के खिलाफ है जो भयानक अँधेरे में डूब चूका है. इस अभियान में उम्मीद की किरणे हैं जो भारत की नई पीढ़ी के लिए ज़रूरी हैं. स्वस्थ, नशा मुक्त भारत अगर नहीं बना तो हम विकसित भारत का सपना देखते रहें, कुछ भी होने-जाने वाला नहीं है. ऐसे में, डॉ. वीरेन्द्र कुमार व डॉ. अमित यादव की ओर से जो बड़े पैमाने पर स्वस्थ व सुन्दर पीढ़ी तैयार करने का यत्न है, उसमें देश के सेवाभावी स्वयंसेवी संगठन, मानवतावादी संगठन व जागरूक समाज की कोशिश जुड़ना अब ज़रूरी है. यदि सभी मिलकर देश से नशामुक्ति के खिलाफ कार्य करेंगे तब ज्यादा सफलता मिलेगी.

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कोथल खुर्द गांव की साहसी सरपंच रोशनी देवी ने पंचायत के सदस्यों और गांव की महिलाओं को शराब की लत के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया और गांव में शराब की एक दुकान को बंद करवा दिया ताकि पुरुष शराब पीकर ऐसी आदतों पर पैसा बर्बाद न करें. बाद में कई गैर सरकारी संगठन भी उनके इस आंदोलन में शामिल हुए. उनके संयुक्त अभियान ने हरियाणा के आबकारी विभाग को दुकान बंद करने के लिए मजबूर कर दिया. तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील, जो हमेशा शराब पीने को पारिवारिक जीवन को नष्ट करने वाली सामाजिक बुराइयों में से एक मानती रहीं, उनके उल्लेखनीय कार्य से प्रभावित हुईं और उन्होंने महिलाओं के पूरे समूह को राष्ट्रपति भवन बुलाया और उनके प्रयासों की सराहना की. पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 जुलाई, 2009 को राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया. सरकार को चाहिए कि ऐसे ग्रुप, व्यक्ति व व्यवस्था को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करे. डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है. पंजाब पीरों की धरती है. पंजाब आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों की धरती है. पंजाब खिलाड़ियों की धरती है. पंजाब जोश से भरे हुए युवाओं की धरती है....देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है. हमारे देश की लगभग 65 प्रतिशत। 878 आबादी युवा है और युवा अगर ठान लेते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकते हैं. बुराइयों के लिए भी खत्म करने के लिए जब हमारा देश का युवा निकलेगा तो नशा मुक्त भारत अभियान जो है ना, नशा मुक्त भारत अभियान भी सफल होगा. मैं आप सब से इसी आशा और विश्वास के साथ में कार्यक्रम के अंत में जब हमारा शपथ का कार्यक्रम होगा तो हम जब शपथ लेकर जाएंगे एक नई सोच के साथ में नई उम्मीद के साथ में कि हमारे इर्दगर्द हमारे आसपास हमारे मित्र जो भी मार्ग से भटक गए हैं उनको सही मार्ग पर लेकर हमको आना है। बस इसे समझने व आत्मसात कर लेने की ज़रूरत है और सरकार का यह दायित्व है कि वे ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित व प्रोत्साहित करें तो परिणाम और अच्छे आएंगे और भारत बन सकेगा नशामुक्त भारत.

टारगेट पूरा हुआ, सर !

कटाक्ष

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सत्तू ने बाइक स्टार्ट की और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा नहीं, बल्कि हेड मास्टर साहब का आदेश एक्सिलेटर पर रखा हुआ है। घड़ी में 9:00 बजने में 15 मिनट बाकी थे, और सत्तू को पता था कि यह 15 मिनट नहीं हैं, यह उसकी नौकरी का, उसकी इज़्ज़त का, और उसकी अगले साल की इंक्रीमेंट का वक्त है। उसने सोचा, 'इतनी तेज़ स्पीड तो मैंने बीवी के कहने पर राशन लाने के लिए भी नहीं पकड़ी, पर साहब! यह सरकारी हाज़िरी का मामला है। यहाँ जान भले ही चली जाए, पर लेट-लतीफ़ी नहीं चलेगी।' उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी; वह नहीं दौड़ रहा था, बल्कि वह उस अदृश्य सरकारी डंडे से भाग रहा था जो हमेशा उसके सिर पर मंडराता रहता था। समय से पहले स्कूल पहुँचकर हाज़िरी देना, यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य था! देश के विकास में भले ही उसका कोई योगदान न हो, पर 9:00 बजे की सेल्फ़ी खींचकर भेज देना, यह उसकी देशभक्ति का परम प्रमाण था। उसकी आँखों के सामने ट्रक नहीं था, बल्कि वह सरकारी अफ़सरशाही का ढाँचा था जो ट्रक की तरह ही ज़बरदस्त और अपनी धुन में चलता है। उसी धुन में सत्तू अंधा हो गया। वह सोच रहा था, बस पाँच मिनट में पहुँचना है, कुर्सी खींचनी है, और मुस्कुराते हुए फोटो खींचना है। मुस्कुराना इसलिए ज़रूरी था, ताकि लगे कि वह ड्यूटी पर पहुँचकर कितना प्रसन्न है, भले ही भीतर से वह सरकारी आदेशों के तले पिस रहा हो।

जब धमाका हुआ, तो सत्तू को कुछ पल के लिए लगा कि हेड मास्टर साहब की घंटी इतनी ज़ोर से क्यों बजी! उसका शरीर हवा में उछला—कैसा मुक्तिबोध! ज़मीन पर गिरने से पहले उसने एक क्षण के लिए ऊपर देखा और सोचा: 'वाह! यह कैसी आज़ादी है! इतने सालों से मैं सरकारी ज़मीन पर पैर टिकाकर खड़ा था, आज हवा में तैर रहा हूँ।' यह सोचने की भी फ़ुरसत न मिली कि वह सिर के बल नीचे आ गिरा। सिर के बल गिरना भी ज़रूरी था, ताकि दिमाग़ में भरा सरकारी तनाव थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। वह उठा नहीं, उठने की कोशिश ज़रूर की—क्योंकि सरकारी कर्मचारी को चोट लगने के तुरंत बाद भी उठकर अपनी ड्यूटी पर पहुँचने का नैतिक दबाव होता है। और फिर वही हुआ जिसकी इस देश में किसी को परवाह नहीं होती—एक तेज़ सरकारी रफ़्तार वाली कार उसे रौंदते हुए निकल गई। यह कार व्यवस्था की रफ़्तार थी, जिसे किसी सत्तू के ज़मीन पर पड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह कार यह साबित करती गई कि ज़िम्मेदार लोग हमेशा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और जो पीछे रह जाता है—चाहे वह ज़िंदा हो या मर गया हो—वह कुचला ही जाता है। सत्तू ने आखिरी बार अपनी टूटी हुई घड़ी को देखा। काँटा 9:00 बजे पर अटक गया था। कमबख्त!

समय पर पहुँचने की इतनी ज़बरदस्त कोशिश की, पर पहुँचने की जगह रुक गया। सत्तू उस दिन समय पर स्कूल नहीं पहुँच सका, यह तो सत्य है। उसकी बाइक और उसका शरीर, दोनों 9:00 बजे से ठीक पहले, बीच सड़क पर स्थायी छुट्टी पर चले गए थे। हेड मास्टर साहब का फ़ोन फिर से आया होगा—'कहाँ हो भाई? फ़ोटो भेजो! हाज़िरी चाहिए!' लेकिन अब सत्तू की हाज़िरी वहाँ लगी थी जहाँ से कोई छुट्टी नहीं मिलती। उस दिन स्कूल में सत्तू का फ़ोटो नहीं खिंचा। सिस्टम को सत्तू की उस मुस्कान वाली हाज़िरी फ़ोटो नहीं मिली, जिसके लिए उसने अपनी जान की बाज़ी लगाई थी। सरकारी कागज़ हमेशा के लिए अपूर्ण रह गया। इस देश में किसी की मृत्यु इतनी पीड़ादायी नहीं होती, जितनी किसी दस्तावेज़ का अपूर्ण रह जाना।

पर विडंबना देखिए! जिस फ़ोटो के लिए वह इतनी तेज़ी से दौड़ा, वह फ़ोटो तो अंततः खिंच गया। उसका एक विशाल फ़ोटो उसके घर में लगा था। बड़ा, माला चढ़ा हुआ, और भव्य! यही वह अंतिम अटेंडेंस थी जिसे सरकार या समाज ने नकारा नहीं। उस तस्वीर के सामने उसके प्रियजन, पड़ोसी, और परिचित श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। ये वही लोग थे जो कल तक उसे कामचोर या सरकारी बाबू कहकर टाल देते थे। विडंबना यह नहीं थी कि सत्तू मर गया, विडंबना यह थी कि सिस्टम को उसकी उपयोगिता तभी समझ आई जब वह फ़ोटो में बदल गया। आह! सत्तू को कितनी खुशी होती, अगर उसे पता चलता कि उसकी एक तस्वीर ने आख़िरकार सबकी श्रद्धा जीत ली, भले ही वह मुस्कुराती हुई ड्यूटी की सेल्फ़ी नहीं थी, बल्कि शोक सभा की हाज़िरी थी। और हाँ, उस बड़े फ़ोटो पर हेड मास्टर साहब भी माला चढ़ाने आए थे, शायद यह देखने कि हाज़िरी की अनिवार्यता का अंतिम नतीजा कैसा दिखता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

यूँ ही कोई विश्वगुरु नहीं बन जाता !

उस हिन्दुस्तानी ख़वातीन की ख़ता बस इतनी सी थी कि वह अमेरिका के इलिनोइस प्रान्त की एक बड़ी सी परचून की दुकान में से मात्र तेरह सौ डॉलर का सामान बिना मूल्य चुकाए ले आई थी. उसने 'चोरी' की थी - पर 'चोरी' कहना मुश्किल है. दरअसल, इन दिनों 'चोरी' कहना ही बेहद रिस्की है. रिस्क चोरी करने, पकड़े जाने में कम है, 'चोरी' का शोर मचाने में अधिक है. कब निज़ाम के कानों में 'चोरी' का स्वर पड़ जाए और बोलने वाला बिहाईंड द बार नज़र आने लगे. इलिनोइस की पुलिस इसे बार-बार थेफ्ट कह रही है सो रिस्क लेकर भी हमें इसे 'चोरी' कहना पड़ रहा है. वहाँ की पुलिस टीम में एक जवान इंडियन ओरिजिन का भी था. विडम्बना यह थी कि भारतीय मूल का होकर भी उसने रिश्वत जैसे उदात्त भारतीय मूल्यों को अभी तक अपने जीवन में अपनाया नहीं था. उससे मिलकर यह अवधारणा ध्वस्त होती है कि राजा हरिश्चंद्र केवल इस पुण्यधरा पर ही अवतरित होते हैं. मैंने उससे कहा - 'अजीब किसम के पुलिसवाले हैं आप! उसे एक चांस देना चाहिए था, वो आपको रिश्वत ऑफर कर पाती. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहें तो मैं.......'

'रिश्वत की पेशकश करके आप एक और क्राईम करेंगे श्रीमान'

मैंने तुरंत ट्रेक बदला - 'मेरी मुवक्किल निर्दोष है. स्टोर में कहीं नहीं लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं. चेतावनी लिखी नहीं होने के कारण ही ख़वातीन सामान छुपाकर ले जाने का साहस कर पाई. ग्राहक के तौर पर उसे प्रॉपरली आगाह किया जाना चाहिए था ताकि वो अतिरिक्त सावधानी से अपने मिशन को अंजाम दे पाती.'

'आपकी मुवक्किल ने चोरी का प्रयास नहीं किया है, चोरी की है श्रीमान'

'बहुत पिछड़ा देश है आपका! हमारे यहाँ तो 'लोकतंत्र की चोरी' होने जैसे आरोप लग लिए और आप लोग हैं कि अभी तक नून, तेल, हल्दी की चोरी जैसे मामलों में अटके पड़े हो! उनने साफ़ कह दिया है शपथपत्र दीजिए तब जाँच करेंगे. आप लोग हैं कि बिना किसी एफिडेविट के फोन पेई चोरी का मुकदमा कायम कर दे रहे हो.'

'आपकी मुवक्किल सामान चुराकर ले जाते हुए बॉडीकैम में स्पष्ट दिखाई पड़ रही है.'

'मैनेजर ने साज़िशन हिडन बॉडीकैम लगाए हैं. परचून की दुकान में गुप्त कैमरे लगाकर मेरी मुवक्किल की निजता का उल्लंघन किया गया है. माताओं बहनों की निजता का ख्याल रखते हुए भारत की संवैधानिक संस्थाएँ सुप्रीम कोर्ट को फुटेज़ मुहैया कराने से मना कर देती हैं और आप हैं कि एक मासूम ख़वातीन को बचाने के लिए बॉडीकैम के फुटेज़ डिलीट नहीं कर पाए. शेम ऑन यू.'

'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे!!' - एक गोरा इंसपेक्टर ताव खा गया. 'यू ब्लडी इंडियंस! अमेरिकंस के जॉब ही नहीं चुराते, कीमती सामान भी चुराते हो. शेम नॉट ऑन अस, शेम ऑन यू.'

'नस्लवादी रवैया अख्तियार कर रहे हैं आप. भारतीयों को फँसाने की कोशिश कर रहे हैं. वो एक ग़रीब पिछड़ी महिला है. इंडिया से पिछड़े और ग़रीब लोग ही वेलिड वीजा लेकर अमेरिका आ पाते हैं. ये सीधा-सीधा ह्यूमन राईट्स का वायोलेशन है.'

'चलिए आप ही बताईए, आपके देश में ये केस कैसे डील होता?'

'मेरी मुवक्किल ने आपको रिपिटेडली सॉरी बोला. इतनी सारी सॉरी'ज में तो पुलिसवाले मैडम को क्लीन चिट दे देते, अपनी जीप से घर तक छोड़कर आते. चोरी को चोरी कहने का ज़माना नहीं रहा इन्स्पेक्टर सा. उसे मूल्य चुकाए बिना सामान घर ले आना कहते है. और हाँ, मैनेजर अगर चोरी चोरी चिल्लाना जारी रखे तो कांस्पीरेसी का मुकदमा मैनेजर पर कायम कर दीजिएगा. एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल.' वे सोच में पड़ गए.

आखिर कुछ तो बात है हम इंडियंस में. यूँ ही कोई विश्वगुरु नहीं बन जाता!

विश्व टेलीविजन दिवस विशेष

ज्ञान, मनोरंजन और भ्रम के बीच टीवी

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ने अपने आविष्कार के करीब 32 साल बाद भारत में पहला कदम रखा। भारत में टीवी का पहला प्रसारण प्रायोगिक तौर पर दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के साथ 15 सितम्बर 1959 को शुरू किया गया। उस समय टीवी पर सप्ताह में केवल तीन दिन ही मात्र तीस-तीस मिनट के कार्यक्रम आते थे लेकिन इतने कम समय के बेहद सीमित कार्यक्रमों के बावजूद भी टीवी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता गया और यह बहुत जल्द लोगों की आदत का अहम हिस्सा बन गया। दूरदर्शन का व्यापक प्रसार हुआ वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के प्रसारण के बाद। दूरदर्शन द्वारा अपना दूसरा चैनल 26 जनवरी 1993 को शुरू किया गया और उसी के बाद दूरदर्शन का पहला चैनल डीडी-1 और दूसरा नया चैनल डीडी-2 के नाम से लोकप्रिय हो गया, जिसे बाद में 'डीडी मैट्रो' नाम दिया गया। भले ही टीवी के आविष्कार के इन दशकों में इसका स्वरूप और तकनीक पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन इसके कार्य करने का मूलभूत सिद्धांत अभी भी पहले जैसा ही है।

वर्ष 1925 में टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर तथा अन्वेषक जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा किया गया था। वे दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1926 को ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूशन से लंदन के पश्चिम में स्थित 'सोहो' नामक स्थान पर टेलीविजन संदेशों का सफल प्रसारण करके दिखाया था। उनके द्वारा बनाए गए मैकेनिकल टेलीविजन के बाद 1927 में फिलो फॉर्न्सवर्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया गया, जिसका 3 सितम्बर 1928 को उनके द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। कुछ असफलताओं के बाद सदी के महान् आविष्कार टेलीविजन को पूरी तरह इलैक्ट्रॉनिक रूप देने में सफलता मिली वर्ष 1934 में। बिजली से चलने वाले उस अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ही बदौलत आगामी वर्षों में कई आधुनिक टीवी स्टेशन खोले दिए जिसके बाद लोग बड़ी संख्या में टीवी खरीदने लगे और टेलीविजन धीरे-धीरे मनोरंजन एवं समाचार का महत्वपूर्ण माध्यम बनता गया।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ने अपने आविष्कार के करीब 32 साल बाद भारत में पहला कदम रखा। भारत में टीवी का पहला प्रसारण प्रायोगिक तौर पर दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के साथ 15 सितम्बर 1959 को शुरू किया गया। उस समय टीवी पर सप्ताह में केवल तीन दिन ही मात्र तीस-तीस मिनट के कार्यक्रम आते थे लेकिन इतने कम समय के बेहद सीमित कार्यक्रमों के बावजूद भी टीवी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता गया और यह बहुत जल्द लोगों की आदत का अहम हिस्सा बन गया। दूरदर्शन का व्यापक प्रसार हुआ वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के प्रसारण के बाद। दूरदर्शन द्वारा अपना दूसरा चैनल 26 जनवरी 1993 को शुरू किया गया और उसी के बाद दूरदर्शन का पहला चैनल डीडी-1 और दूसरा नया चैनल डीडी-2 के नाम से लोकप्रिय हो गया, जिसे बाद में 'डीडी मैट्रो' नाम दिया गया। भले ही टीवी के आविष्कार के इन दशकों में इसका स्वरूप और तकनीक पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन इसके कार्य करने का मूलभूत सिद्धांत अभी भी पहले जैसा ही है। 'ब्लैक एंड व्हाइट' बुद्धू बक्सा अपने सहज प्रस्तुतिकरण के दौर से गुजरते हुए कब आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए सूचना क्रांति का सबसे बड़ा हथियार और हर घर की अहम जरूरत बन गया, पता ही नहीं चला। यह दुनिया जहान की खबरें देने और राजनीतिक गतिविधियों की सूचनाएं उपलब्ध कराने के अलावा मनोरंजन, शिक्षा तथा समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने, प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समूचे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करने वाला एक सशक्त जनसंचार माध्यम है। यह संस्कृतियों और रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान के रूप में मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है, जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरी दुनिया के ज्ञान में असीम वृद्धि करने में मददगार साबित हो रहा है। मानव जीवन में टीवी की बढ़ती भूमिका तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को 'विश्व टेलीविजन दिवस' मनाया जाता है।

संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसके महत्वों को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विश्व टेलीविजन दिवस' मनाने की जरूरत महसूस की गई और आम जिंदगी में टीवी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आखिरकार टीवी के आविष्कार के करीब सात दशक बाद वर्ष 1996 में 'विश्व टेलीविजन दिवस' मनाने की घोषणा कर दी गई। दरअसल टीवी के आविष्कार को सूचना के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का आविष्कार माना गया है, जिसके जरिये समस्त दुनिया हमारे करीब रह सकती है और हम अब घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं को लाइव देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 21 तथा 22 नवम्बर 1996 को विश्व टेलीविजन मंच का आयोजन करते हुए टीवी के महत्व पर चर्चा करने के लिए मीडिया को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था। उस दौरान विश्व को परिवर्तित करने में टीवी के योगदान और टीवी के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में व्यापक चर्चा की गई थी। उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17 दिसम्बर 1996 को एक प्रस्ताव पारित करते हुए प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और तभी से प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को ही यह दिवस मनाया जाता रहा है। हालांकि किसी भी वस्तु के अच्छे और बुरे दो अलग-अलग पहलू भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही सूचना एवं संचार क्रांति के अहम माध्यम टीवी के मामले में भी है। एक ओर जहां यह मनोरंजन और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है और नवीनतम सूचनाएं प्रदान करते हुए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते रहे हैं। टेलीविजन की ही वजह से ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि तमाम क्षेत्रों में बच्चों से लेकर बड़ों तक की सभी जिज्ञासाएं शांत होती हैं। अगर नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो टीवी के बढ़ते प्रचलन के साथ-साथ इस पर प्रदर्शित होते अश्लील, हिंसात्मक, अंधविश्वासों का बीजारोपण करने तथा भय पैदा करने वाले कार्यक्रमों के कारण हमारी संस्कृति, आस्था और नैतिक मूल्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। टीवी पर विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार हत्या और बलात्कार जैसे दृश्य दिखाने से बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। मौजूदा समय में टीवी मीडिया की सबसे प्रमुख ताकत के रूप में उभर रहा है और मीडिया का हमारे जीवन में इस कदर हस्तक्षेप बढ़ गया है कि टीवी के वास्तविक महत्व के बारे में अब लोगों को पर्याप्त जानकारी ही नहीं मिल पाती।

देश में जहां दूरदर्शन की शुरूआत के बाद दशकों तक दूरदर्शन के ही चैनल प्रसारित होते रहे, वहीं 1990 के दशक में निजी चैनल शुरू होने की इजाजत मिलने के साथ एक नई सूचना क्रांति का आगाज हुआ। इन तीन दशकों में निजी चैनलों को लगातार मिलते लाइसेंस के चलते अब देशभर में टीवी पर करीब एक हजार चैनल प्रसारित होते हैं। इससे दूरदर्शन जैसे माध्यम कमजोर हो गए हैं और अब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां सूचना व संचार माध्यमों ने हमें इस कदर अपना गुलाम बना लिया है कि इनके अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि ढ़ेर सारे टीवी चैनलों की बदौलत जहां ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, सूचना आदि के स्रोत बढ़े हैं, वहीं चिंताजनक स्थिति यह है कि टीआरपी की बढ़ती होड़ में बहुत से निजी टीवी चैनल जिस प्रकार गलाकाट प्रतिद्वंद्विता के चलते समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हुए दर्शकों के समक्ष कुछ भी परोसने को तैयार रहते हैं, उससे युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है और जनमानस में गलत संदेशों का बीजारोपण होता है। इसीलिए मांग उठने लगी है कि दिशाहीन टीवी कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों पर अंकुश लगाने और अपसंस्कृति के प्रसार को रोकने के लिए इन पर कुछ कड़े कानूनी प्रतिबंधों का प्रावधान होना चाहिए।

कानून का दुरूपयोग

'सरफेसी एक्ट' से अवैध कब्जे का गोरख धंधा

ऋषि कुमार सोलंकी

(हाईकोर्ट एडवोकेट)

'सरफेसी एक्ट 2002' ऐसा कानून है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखी संपत्तियों को नीलामी के ज़रिए बेचकर बिना अदालत जाए ऋण की वसूली करने की शक्ति देता है। जब कोई उधारकर्ता लगातार कर्जों की किस्त चुकाने में विफल रहता है और खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित हो जाता है, तो यह कानून बैंकों को कार्रवाई करने की अनुमति देता है। 'सरफेसी एक्ट' के तहत, बैंकों को संपत्ति जब्त करने के लिए किसी सिविल कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

सरफेसी आडिनेस एक्ट 21 साल पहले लागू किया गया। इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थानों के मानदंडों को पूरा करने के बाद एक्ट अनुसार मॉडगेज्ड या सिक्योरिटी एसेट के कब्जे का प्रावधान है। बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा सरफेसी एक्ट में कार्यवाही के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उनके द्वारा किसी इररेगुलर/ ड्यू-बट-नॉट पेड खाता जो 90 दिन से अधिक होने को आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज (एनपीए) की शर्तों के पालन में नॉट पेड अवधि के लाभ को बैंक के लाभ/हानि खाते से रिवर्स करना होता है। ऐसे में उस खाते में कोई भी लाभ की एंट्री नही की जा सकती है। लेकिन, बैंक या वित्तीय संस्थानों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इररेगुलर अकाउंट जो कि 90 दिन से अधिक अवधि के है, को बिना एनपीए क्वालीफाई किए कलेक्टर व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष धारा 14-1 के सपोर्ट में झूठे शपथ पत्र देकर अवैधानिक कब्जे की कार्यवाही की जा रही है। आम जनता के मॉडगेज मकान, दुकान या संपत्तियों पर अवैधानिक कब्ज़ा करके धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।

बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी खाते को एनपीए क्लासीफाय किया गया है कि नहीं उसे खातेदार के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्लासिफिकेशन की तारीख कि लाभ की रिवर्स एंट्री तथा उक्त एनपीए के दिन के बाद किसी भी अगली एंट्री के न होने पर देखकर निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन, कई बैंक व वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने इस झूठ को छुपाने के लिए खातेदार को कलेक्टर को दिए कब्जे के आवेदन में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कि डेट वाइज होता है की जगह फोरक्लोजर अकाउंट स्टेटमेंट दिया जाता है, जिससे क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बैंक, वित्तीय संस्थाएं यदि किसी इररेगुलर या ड्यू-बट-नॉट पेड खाते को यदि क्लासीफाय नहीं करता, तो वह सिर्फ ड्यू बट नॉट पेड राशि की ही मांग कर सकता है। लेकिन, सरफेसी एक्ट की आड में यह जानते बुझते कि खाता क्लासिफाइड, एनपीए नहीं है बैंक द्वारा पूरी आउटसेडिंग राशि का चेक बाउंस कराते हैं और उनके खाते धारकों को प्रताड़ित करने के लिए विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं।

बैंक व वित्तीय संस्थाओं का व्यवसाय महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों के साथ ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनसे इसके बदले लाभ स्वरूप ब्याज प्राप्त करना है न कि धड़ल्ले से झूठे शपथ पत्र के जरिए मॉडगेज्ड संपत्तियों को अवैधानिक रूप से बेचना। धारा 14-1 के आवेदन व सरफेसी एक्ट की कार्यवाही जहां चालू की गई, वहां उनके द्वारा एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं किया गया और अवैधानिक कब्जे को प्राप्त कर अधिकतर संपत्तियो को अवैधानिक रूप से बेचा गया।

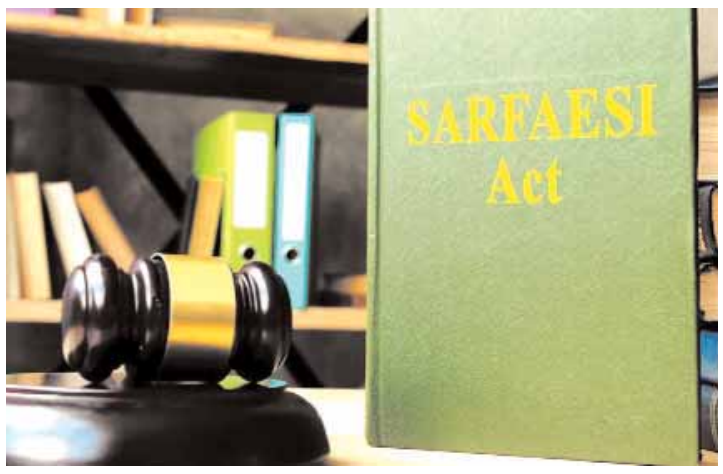

किसी भी ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग/क्वासी ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग में जानबूझकर झूठा शपथ पत्र दिया जाना एक गंभीर श्रेणी का अपराध है तथा इसमें न्यायिक प्रणाली में सजा का स्पष्ट प्रावधान है।

ऐसे ही एक केस में न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया गया। साथ ही आम जनता के राइट-टू प्रॉपर्टी और लाइक्लीहुड के संवैधानिक अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह कभी नहीं माना जा सकता कि सरफेसी एक्ट अंतर्गत किसी प्राधिकृत अधिकारी को शपथ पत्र देने के पहले यह जानकारी न हो या वह इसके निर्धारण करने में असमर्थ है। क्योंकि, एक्ट के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी किसी नेशनलाइज्ड बैंक के चीफ मैनेजर से कम नहीं हो सकता जो कि शडयुल टू बैंक व वित्तीय संस्थानों के मामले में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट से कमतर नहीं हो सकता। अतः यह एक सोचा समझा कृत्य ही है, जो उनके खातेगार की कास्ट पर किया जा रहा है तथा उन्हें आवश्यक रूप से दंडित किया जाना चाहिए जिससे इस कार्य की पुनरावृत्ति न हो।

बैंक व वित्तीय संस्थानों ने जहां बिना क्लासिफिकेशन या सरफेसी एक्ट के अन्य प्रावधानों को पूरा किए बगैर कार्यवाही शुरू की है, कि जांच उच्चतम न्यायालय की देखरेख में आरबीआई की गठित समिति द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी बैंक व वित्तीय संस्थानों पर कठोरतम कार्यवाही (संगनमत अधिकारियों को व्यक्तिगत दंड/बैंक व वित्तीय संस्थानों पर वित्तीय दंड जो कि खातेदार को मानसिक प्रताड़ना के एवज में प्राप्त हुए) किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा जहां बैंक व वित्तीय संस्थानों ने जानबूझकर कथित झूठे शपथ पत्रों की आड़ में अवैधानिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया। ऐसे मामलों में प्रदेश स्तर पर उच्च न्यायालय व संभाग कमिश्नर की देखरेख में जिला वार समिति द्वारा जांच किया जाकर ऐसे कब्जों के सभी आदेशों को एक बार निरस्त किया जाना चाहिए।

जहां बैंक व वित्तीय संस्थानों द्वारा या तो अवैधानिक कब्जा आदेश के साथ या बगैर मॉडगेज संपत्तियों को 'सरफेसी एक्ट' के अंतर्गत आरक्षित किया गया है। उसे प्रादेशिक रूप से उच्च न्यायालय की देखरेख में व उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति, आरबीआई या बैंक के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी व इस विधा के किसी वरिष्ठ चार्टेट अकाउंटेंट व अन्य सदस्यों की समिति द्वारा जांच की जाना चाहिए। इसके बाद अवैधानिक ऑक्शन को निरस्त कर, आम जनता को सरफेसी एक्ट धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजा दिया जाना निर्धारित किया जाना चाहिए। यह कार्य ऐसे मामलों में किया जाना चाहिए जो बैंक व वित्तीय संस्थानों के जानबूझकर किए है और जिसमें विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग स्पष्ट दिखता है।

प्रकाशन बाजार

लेखकों, कवियों और प्रकाशकों का गर्माता बाजार

प्रो. डॉ. वत्सला

लेखक एवं शिक्षाविद् हैं

साहित्य जगत में एक नई प्रवृत्ति पनप गई, वह है साहित्यकारों द्वारा अपनी रचनाओं के प्रकाशन की। पहले तो प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की रचनाओं का प्रकाशन बड़ी मुश्किल होता था। लेकिन, वर्तमान में प्रकाशन का बाजार खुल गया। साझा संकलनों के प्रकाशन का भीड़ तंत्र इकट्ठा हो गया है। साझा संकल न के संपादक और प्रकाशक साहित्यकारों के व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपना विज्ञापन मय शुल्क के प्रेषित कर देते हैं। वर्तमान में साहित्यकारों को किताबों में छपने का रोग हो गया है।

आज साहित्य में जो कविता या कहानी या अन्य विधाएं लिखी जा रही हैं अपवाद स्वरूप कुछ एक को छोड़कर शेष को हम स्तरीय साहित्य नहीं कह सकते हैं। आज मोबाइल के एप यथा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि तथा इन पर निर्मित विभिन्न साहित्यिक पटल कविता लिखने के प्रकाशक एवं प्रकाशन विभाग बन गए। कवि और लेखक बनने की चाह में जो भी मनोभाव हृदय स्थल से निकलते हैं, अपनी सारी संवेदनाओं को कवि और लेखक इन साधनों पर टंकित कर देते हैं और कवि बन जाते हैं। ध्वन्या लोककार आनंदवर्धन ने कहा है 'अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।' अर्थात् इस अनंत काव्य जगत में (उसका निर्माता) केवल कवि ही एक प्रजापति (ब्रह्मा) है उसे जैसा अच्छा लगता है यह विश्व इस प्रकार बदल जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्राणियों/जीवों से किया है वैसे ही आज कवि बनने की चाहत में काव्य के नए जगत का निर्माण किया जा रहा हैं।

आज नवोदित रचनाकार व गृहस्थ महिलाएं जिन्हें कविता की संरचना कैसे की जाती है, नहीं पता। उन्हें कविता के विधान का ज्ञान नहीं है, किंतु तुकबंदी करके कुछ भी लिखकर कवि और कवयित्री बनते जा रहे हैं और इनकी संख्या दिन-ब-दिन बरसाती पानी से भरे तालाब में टर्र टर्र बोलने वाले मेंढकों की भांति बढ़ती जा रही है। कबीर अनपढ़ थे तो वे स्वीकार करते थे 'मसि कागद छुओ नहीं कलम गहि नहि हाथ' उन्होंने पंचमेल भाषा में जो भी उपदेश दिया, वह समाज को जागरूक करने के लिए दिया। जनता ने उनके उपदेशों से सीख भी ग्रहण किया। लेकिन, वर्तमान में कुछ कवि समवाय को छोड़कर शेष लोग लिखने व छपने की होड़ में कुछ भी लिखकर कवि और लेखक बनते जा रहे हैं। यह स्थिति साहित्य के लिए चिंता का विषय है।

वर्तमान में साहित्य जगत में एक नयी प्रवृत्ति पनप गई है वह है साहित्यकारों द्वारा अपनी रचनाओं के प्रकाशन की। पहले तो प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की रचनाओं का प्रकाशन बड़ी मुश्किल होता था। लेकिन, वर्तमान में प्रकाशन का बाजार खुल गया। साझा संकलनों के प्रकाशन का भीड़ तंत्र इकट्ठा हो गया है। साझा संकलन के संपादक और प्रकाशक साहित्यकारों के व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपना विज्ञापन मय शुल्क के प्रेषित कर देते हैं। वर्तमान में साहित्यकारों को किताबों में छपने का रोग हो गया है। इन विज्ञापनों में धनराशि की श्रेणियां अलग-अलग होती हैं। आपकी जेब जितना बर्दाश्त कर लें उतनी धनराशि प्रेषित कर आप पुस्तक में छप जाइए और गौरवान्वित महसूस कीजिए।

साझा संकलनों के प्रकाशक पुस्तक का विमोचन करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे तथा पुस्तक की एक प्रति प्रदान करेंगे। उनके विज्ञापनों में विमोचन समारोह की भी सूचना दी जाती है। आज महिला तथा पुरुष दोनों साहित्यकार छपने से अछूते नहीं रहना चाहते। विमोचन के बाद पुस्तक की प्रति सबको वितरित की जाती है। कुछ लोग उसे उलट-पलट कर देखते हैं, देखने पर टंकण की अशुद्धि और व्याकरणात्मक त्रुटियों को देखकर अलमारी में रख देते हैं। फिर ये पुस्तकें केवल अलमारी की शोभा बन जाती हैं। लेकिन, ये साहित्यकार बहुत ही गर्व से कहते हैं कि मेरे साझा संकलनों की संख्या इतनी और इतनी किताबें हो गई हैं, मानो किताबों की संख्या पर सरकार की कोई नई योजना आई हों। साझा संकलन के संपादक लेशमात्र भी कष्ट नहीं उठाते हैं कि आई हुई रचनाओं को देख लें और उसमें सुधार कर दें यथा स्थान जहाँ अशुद्ध हों। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर वे लिख देते हैं कि किसी भी त्रुटि के लिए संपादक की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसा लिखकर फिर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। प्रकाशक व संपादक उभय के लिए साझा संकलन अर्थ राशि अर्जित करने का व्यापार हो गया है।

आनंद की बात तो यह है कि इन साझा संकलनों की लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों के मुख से प्रशंसा भी नहीं सुनी जाती हैं। कालिदास ने लिखा है 'आपरितोषाद् न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्' अर्थात् जब तक विद्वानों को संतुष्टि न हो जाए तब तक अपने नाटक के प्रयोग को सफल नहीं मानता हूं। इसी प्रकार जब तक इन संकलनों में प्रकाशित कविताओं की प्रशंसा साहित्य मर्मज्ञ न करें तब तक ये संकलन केवल अलमारी में रखें रजकणों से परिपूर्ण रहेंगे। ऐसे संकलनों में प्रकाशित होकर अपने को कवि मान लेना, यह तो केवल आत्ममुग्धता है। जिसका शिकार आज बहुत से साहित्यकार हो गए हैं। कवि प्रतिभा सभी में नहीं होती, अग्निपुराण कार का कथन है- 'नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा' कवित्व से भी दुर्लभ कवित्व की प्रतिभा होती है। श्रेष्ठ कवि वही है जिसमें उभय गुण विद्यमान हों। लेकिन, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कवियों के सौ प्रकार बताए हैं। आज समाज में ऐसे ही नाना प्रकार के कवि उभरते जा रहे हैं।

राजशेखर ने कवियों की कई श्रेणियाँ बताई हैं यथा शास्त्र कवि, काव्य कवि, उभय कवि, रचना कवि, शब्द कवि, अलंकार कवि, अर्थ कवि, भक्त कवि, रस कवि, मार्ग कवि, शास्त्रार्थ कवि, सारस्वत, अभ्यासिक, उपदेशिक आदि। आज कविता लिखने व सुनाने को आतुर कवियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। काव्य गोष्ठियों या कवि सम्मेलनों में मंचों से जब कवियों के नाम की उद्घोषणा की जाती है कि अपनी प्रतिनिधि रचना सुनाएं। किंतु रचना सुनाने को आतुर कविगण माइक छोड़ते ही नहीं है। वर्तमान में कवि भी कई श्रेणियां में बंट गए हैं। कुछ अति अभिमानी होते हैं, उन्हें अपनी रचना लेखन पर बहुत अहं रहता है, वह नवोदित रचनाकारों का मार्ग भी प्रशस्त करना नहीं चाहते हैं। कुछ स्वान्तः सुखाय लिखते हैं, कुछ केवल तुकबंदी करने वाले होते हैं, कुछ केवल अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं, चाहे वे भाव कैसे भी हो। गाजर घास की भाँति कविगण यत्र, तत्र ,सर्वत्र पनपते जा रहे हैं।

कतिपय नवोदित व अंकुरित कवि जो बहुत वैभवशाली हैं, वे स्वयं पुस्तकें प्रकाशित कर साहित्य मर्मज्ञों की श्रेणी में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में अमुक कवि की दृष्टि और अमुक कवि की सृष्टि की परंपरा हो गई है। आज कवियों के लिए अनेक रजिस्टर्ड पटल व्हाट्सएप पर खुल गए हैं। इन पटलों पर साहित्यिक कार्यक्रमों की बाढ़ आयी हुई है। हर साहित्यकार न जाने कितने पटलों से जुड़ा है, शायद उसे भी नहीं पता होगा। पटल के संस्थापक रचनाकारों को काव्य पाठ एवं सम्मान प्रदान करने का अवसर भी देते हैं। आज सम्मान व पुरस्कार उफनती नदी की तरह उफान पर हैं। हर साहित्यकार के पास सम्मानों का जखीरा इकट्ठा हो गया है। आनंद की बात तो यह है कि यह सम्मान व पुरस्कार भी साहित्यकार से ही धनराशि एकत्रित कर दिया जाता है। यदा-कदा कवियों को स्मृति- चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। सम्मान भी बड़े-बड़े कवियों के नाम से दिया जाता है।

बेचारे स्मृति शेष, कालजयी साहित्यकार अपने नाम की दुर्दशा को देखकर आकाश में विलाप करते होंगे। सम्मान देने वाले कवियों की योग्यता का आकलन किए बिना ही सम्मान प्रदान कर रहे हैं। एक समय में सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ था किंतु आज सर्वजन सुलभ हो गया है। कवियों और साहित्यकारों के भेड़चाल पर नियंत्रण लगाना होगा, वरना निरर्थक साहित्य से पुस्तकालय जब आपूर्ण हो जाएगा और कोई आततायी उसमें आग लगाएगा तो यह किताबें भी नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की तरह छः महीनों तक जलती रहेगी। कीचड़ में कमल भी खिलता है। कवियों के गड्डुलिका प्रवाह में भी कई नवोदित रचनाकार अच्छा लेखन कार्य कर रहे हैं। लेकिन, भीड़ में उनके अस्तित्व पर भी संकट के बादल छाए हैं। ऐसे कवियों को अपना स्थान बनाने के लिये अनथक प्रयास करना होगा।

मृत व्यक्ति के खाते से भी ट्रांजैक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा

बैंक के 7 खातों से 9.84 करोड़ की साइबर ठगी

बैतूल। पुलिस और साइबर सेल ने करीब 9 करोड़ 84 लाख रुपये की एक संगठित साइबर ठगी का खुलासा किया है। साइबर लूट के इस मामले के आरोपी मृत व्यक्ति के खाते से लगातार रकम का भी लेन-देन कर रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि बैतूल में एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति बिसराम इवने (40) निवासी खेड़ी सावलीगढ़ (थाना कोतवाली) ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय बैतूल में लिखित आवेदन देकर बताया था कि उसके जन-धन खाते में लगभग 2 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन दिखाई दे रहे हैं, जिनकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। जब वह बैंक में केवायसी कराने गया, तभी उसे इन भारी-भरकम ट्रांजेक्शनों का पता चला। शिकायत की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशानुसार साइबर सेल ने जांच प्रारंभ की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जून 2025 से अब तक उसके खाते से लगभग 1.5 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन किया गया था। एक ही बैंक के 7 अलग-अलग खाता धारक बिसराम इवने, नर्मदा इवने, मुकेश उइके, नितेश उइके, राजेश बर्डे, अमोल और चंदन के बैंक खातों को निशाना बनाते हुए गिरोह ने 9,84,95,212 रुपये की हेराफेरी की। इन खाताधारकों में मृत व्यक्ति का नाम देखकर जांच टीम भी चौंक उठी। गिरोह ने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए मृत व्यक्ति राजेश बरडे के खाते का भी किया इस्तेमाल किया। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक राजेश बर्डे के खाते का उतनी ही सक्रियता से उपयोग किया जा रहा था, जैसे कोई जिंदा ग्राहक करता है।

मोबाइल नंबर बदला, जारी कराया एटीएम कार्ड – गिरोह ने खाते का मोबाइल नंबर बदला और एटीएम कार्ड जारी करवाया। इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस लिया और ओटीपी पर कब्जा जमाया। मृत व्यक्ति के खाते से लगातार ऊंची रकम के लेनदेन किए। पुलिस ने जांच में पाया गया कि बैंक में पासबुक एंट्री करने वाला एक टेंपरेरी कर्मचारी ही इस गिरोह का मुख्य सहयोगी था। जिसकी सहायता से गिरोह के हाथ बैंक शाखा की गोपनीय ग्राहक जानकारी तक पहुँच चुके थे, जिसके जरिए पूरी वित्तीय फर्जीवाड़े की मशीनरी चलाई गई। बैंक कर्मचारी ने ग्राहक दस्तावेजों से छेड़छाड़, खातों में फर्जी मोबाइल नंबर लिंक कराना, एटीएम कार्ड जारी कराना और पासबुक/चेकबुक का अनधिकृत उपयोग जैसे कार्यों के जरिए गिरोह को खातों तक अंदरूनी पहुंच उपलब्ध कराई।

खातों की जानकारी भेजी जाती थी इंदौर

मुख्य अपचारी राजा राजपूत ने बैंक में काम करते हुए कई खातों की संवेदनशील जानकारी अवैध रूप से हासिल की।

इसके तार जिले से बाहर बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े पाए गए। यह खाते की पूरी किट इंदौर भेजी जाती थी। गिरोह प्रत्येक लक्षित खाते की एक किट तैयार करता था, जिसमें लिंक की गई सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक शामिल रहती थी। यह किट बस के माध्यम से इंदौर भेजी जाती थी, जहाँ से बाहरी फ्रॉडिस्टर बड़े ट्रांजेक्शन को अंजाम देते थे। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इंदौर में आरोपियों के दो ठिकानों पर दबिश दी और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों के पास से जब्त की यह सामग्री

पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 15 मोबाइल फोन (25 सिम सहित), 21 एटीएम कार्ड, 28,000 नगद, 11 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 2 पीओएस मशीन, 69 एटीएम, जमा रसीदें (21 लाख जमा), 48,000 की जमा पर्ची, 2 लैपटॉप, 1 फाइबर राउटर, 4 रजिस्टर व डायरी (रिकॉर्ड) जब्त कर राजा उर्फ आयुष चौहान (28) निवासी खेड़ी सावलीगढ़, अंकित राजपूत (32) निवासी इंदौर और नरेंद्र सिंह राजपूत (24) निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में बैतूल पुलिस की तकनीकी दक्ष साइबर सेल टीम ने काम किया। टीम में कोतवाली टीआई नीरज पाल सहित कई अनुभवी एसआई व तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे।

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि इस जटिल साइबर ठगी को टीम ने तकनीकी दक्षता और बेहतरीन तालमेल के साथ उजागर किया। जिले के बाहर की गई कार्रवाई में भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। एएसपी कमला जोशी ने बताया कि जब्त डिजिटल सामग्री के विश्लेषण से गिरोह का नेटवर्क और स्पष्ट हो रहा है। जप्त उपकरणों का फॉरेंसिक विश्लेषण जारी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। मृतक राजेश बर्डे के खाते की पूरी ट्रांजेक्शन चेन तैयार कर रहे है।

इनका कहना है –

इस जटिल साइबर ठगी को टीम ने तकनीकी दक्षता और बेहतरीन तालमेल के साथ उजागर किया। जिले के बाहर की गई कार्यवाही में भी टीम ने शानदार प्रोफेशनलिज्म का प्रदर्शन किया है। जब्त उपकरणों का फॉरेंसिक विश्लेषण जारी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

– वीरेन्द्र जैन, एसपी, बैतूल

पढ़ाने के लिए शिक्षक और पीने के लिए पानी नहीं

छात्राएं बोलीं– स्कूल जाकर क्या करें विज्ञान, गणित के शिक्षक एसआईआर में

आमला। गुरुवार को नगर के मेन रोड स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं पीने के पानी के लिए यहां वहां भटक रही थी। पूछने पर पता चला कि बीते दो दिनों से स्कूल में पीने का पानी नहीं है। छात्राओं ने बताया कि पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं है। ऐसे में जब यहां व्यवस्था बेहतर होगी, स्कूल आएंगे, नहीं तो कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेंगे।

कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऐसे हालत क्यों बन रहे हैं कि छात्राओं को कहना पड़ रहा है कि पीने के लिए पानी नहीं है और पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं है, जो व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दे कि इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण के कार्यों में शिक्षकों को लगाया गया है। इनमें ज्यादातर ऐसे शिक्षक भी शामिल है, जो स्कूलों में गणित और विज्ञान जैसे जटिल विषयों को पढ़ाते हैं। जिससे स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ही नहीं बल्कि सी.एम.राइस हायर सेकेंडरी स्कूल के भी गणित और विज्ञान के शिक्षकों को एसआईआर में लगाने से स्कूलों में अध्ययन व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पीने की पानी की समस्या होने से भी छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है।

फरवरी मार्च में होना है परीक्षा – एसआईआर प्रक्रिया में लगे शिक्षकों से स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह लडख़ड़ा गई है। आगामी दो तीन महीनों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के इम्तिहान भी होना है, किंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यवस्था नहीं बनाने से समस्याएं हो रही है, ऐसे में छात्र-छात्राएं और शिक्षक भी अब इम्तिहानो का समय आगे बढ़ाए जाने की वकालत कर रहे हैं।

इनका कहना है –

नगरपालिका द्वारा दो दिनों से पानी की आपूर्ति बंद किए जाने से पानी की समस्याएं आ रही है। नपा ने कहा है कि पाइपलाइन फूट गई है, इसलिए दिक्कत हो रही हैं। स्कूल के कुछ शिक्षक एसआईआर में लगे है, लेकिन हम व्यवस्था बना रहे हैं।

– प्रमिला सावले, प्रिंसिपल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमला

स्कूलों में व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। शिक्षकों को एसआईआर में लगाने से व्यवस्था कहीं-कहीं गड़बड़ जरूर हुई है, फिर भी मिलाकर कक्षाएं लगाने के लिए स्कूलों को कहा गया है। मैं खुद भी व्यवस्था देख रहा हूं।

– धीरेंद्र साहू, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आमला।

जिले में 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक चलेगा पुरूष नसबंदी पखवाड़ा

बैतूल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 21 नवम्बर से पुरूष नसबंदी पखवाडा प्रारंभ किया गया है, जो आगामी 4 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। इस वर्ष की थीम आज ही शुरूआत करें, पति-पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें निर्धारित है। पुरूष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन दो चरणों में क्रियान्वित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि प्रथम चरण में 21 से 27 नवम्बर तक लक्ष्य दम्पत्तियों से भेंट कर उन्हें नसबंदी कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। द्वितीय चरण 28 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक सेवा प्रदायगी सप्ताह में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुरूष नसबंदी शिविर आयोजित किए जाएंगे। सीएमएचओ डॉ मनोज कुमार हुरमाडे ने समस्त मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मोबेलाईजेशन एवं सामाजिक जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करें। पुरूष नसबंदी के लिए इच्छुक दम्पत्तियों का चिन्हांकन करें। पुरूष नसबंदी के प्रति समाज की धारणा में बदलाव लाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाए। पुरूष नसबंदी के लाभ के संबंध में समझाइश दी जाए,ताकि स्वेच्छा पूर्वक पुरूष नसबंदी अपनाने के लिए हितग्राही आगे आएं। परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनों की जानकारी प्रदाय कर अधिक से अधिक पुरूषों की सहभागिता बडाई जाए। उन्होंने बताया कि पुरूष नसबंदी एक बहुत ही विश्वसनीय, आसान, स्थायी एक छोटा सा ऑपरेशन है, जिसमें अस्पताल में रूकने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोनों ओर की शुक्रवाहिनी नली को काटकर दोनों सिरों को बांध दिया जाता है, नसबंदी बिना चीरा, बिना टांके के 10 से 20 मिनट में पूरी की जाती है। पुरुष नसबंदी कराने वाले हितगाही के लिए 3 हजार रुपए एवं प्रेरक को 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।

सांस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय उन्मुखीकरण का आयोजन

बैतूल। सांस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी बैतूल में गुरुवार को बीएमओ, बीपीएम, बीईई, बीसीएम का जिला स्तरीय उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कुमार हुरमाडे ने बताया कि सांस अभियान शासन के दिशा निर्देशानुसार जिले में 12 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों में सबसे अधिक मृत्यु का कारण निमोनिया संक्रमण है। वर्तमान में 5.1 प्रति हजार बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण हो जाती है, जिसे 3 प्रति हजार जीवित जन्म से कम किया जाना है। सांस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में समुदाय एवं संस्था स्तर पर संभावित निमोनिया के प्रकरणों की सही समय पर पहचान, प्रोटोकॉल्स अनुसार उपचार एवं आवश्यकता प?ने पर उचित संस्था में रैफरल, समुदाय में निमोनिया की रोकथाम, बचाव एवं उपचार के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, समुदाय में निमोनिया के प्रति कुरीतियों एवं अंधविश्वास में कमी लाना, सामाजिक जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्रदान किया जाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आशा द्वारा घर-घर जाकर गृह भेंट कर बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई व निमोनिया के लक्षण की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पहचान व प्रबंधन कर एएनएम व सीएचओ को सूचित करेगी। सीएचओ, एएनएम, मेडिकल ऑफिसर, आरबीएसके मेडिकल ऑफिसर द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान एवं उपचार किया जाएगा। साथ ही मातृ बैठकों का आयोजन कर स्वच्छ ईंधन का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, शीघ्र उपचार, स्तनपान, पूरक आहार एवं खतरे के लक्षणों की जानकारी दी जाएगी। गंभीर बच्चों को उचित स्वास्थ्य संस्था पर रेफर किया जाएगा। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी शहरी चिकित्सा अधिकारी, डीपीएम डॉ विनोद शाक्य, एमएण्डईओ, डीसीएम, बीपीएम, बीईई, बीसीएम, आरबीएसके मैनेजर आदि मौजूद रहे।

जिले के 4 लाख 89 हजार 298 मतदाताओं ने गणना पत्रक किए जमा

बैतूल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के गणना चरण अंतर्गत बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर घर-घर जाकर एप में डिजिटाईज करने का कार्य लगातार कर रहे है। गुरुवार दोपहर तक जिले में करीब 4 लाख 89 हजार 298 मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक जमा कर दिये है, जिन्हे बीएलओ एप डिजिटाईज भी कर दिया है। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर लगातार कार्य कर गणना प्रपत्रों को प्राप्त कर रहे है। गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की जो जानकारी भरी जाना है व बैतूल जिले में पूर्व से ही 78 प्रतिशत मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मेपिंग कर ली गई थी, जो पूर्व से बीएलओ के पास उपलब्ध है, जिससे मतदाताओं को अपना गणना प्रपत्र भरने में सुविधा है। जिन मतदाताओं के पास 2003 की जानकारी नहीं है। ऐसे मतदाताओं के लिए जिले मे 22 हेल्पडेस्क मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए गए है, जिनमें बैतूल में 04, आमला में 04, मुलताई 01, घोड़ाडोंगरी 06, भैंसदेही 07 है।

क्षेत्र के 19 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होगी शव संरक्षण फ्रिज सुविधा

विधायक के प्रयासों से मिली प्रशासनिक स्वीकृति

बैतूल/मुलताई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलताई और प्रभात पट्टन सहित मुलताई क्षेत्र के कुल 19 उप स्वास्थ्य केंद्रों में अब शव संरक्षण फ्रिज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा विधायक चंद्रशेखर देशमुख के प्रयासों से संभव हो पाई है, जिनके माध्यम से प्रमुख स्वास्थ्य भवनों में शव संरक्षण फ्रिज क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से शव संरक्षण फ्रिज की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। प्रत्येक शव संरक्षण फ्रिज की अनुमानित लागत 1.98 लाख बताई गई है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त प्रमुख उप स्वास्थ्य केंद्रों में बिसनूर, मासोद, बिरुल बाजार, बरखेड़ा, अमरावती घाट, तिवरखेड़, साईखेड़ा, गेहूं बारसा, घाट बिरोली, चिचंडा, आष्टा, सालबर्डी सहित अन्य केंद्र शामिल हैं।

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत– अब तक शव संरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालांकि कुछ समाजसेवी संगठनों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती थी, लेकिन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप वह पर्याप्त नहीं थी। उप स्वास्थ्य केंद्रों को नई सुविधा की स्वीकृति मल जाने से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।

क्या है शव संरक्षण फ्रिज?

शव संरक्षण फ्रिज एक अत्याधुनिक शीतक यंत्र है, जिसका उपयोग अस्पतालों और पोस्टमार्टम गृहों में किया जाता है। इसमें शवों को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जाता है, जिससे परिजनों को आवश्यक समय और प्रशासन को उचित प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलता है।

एंबुलेंस में गोवंश तस्करी, 10 मवेशी बरामद, वाहन जब्त, चालक फरार

बैतूल/मुलताई। मासोद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एंबुलेंस में ले जाए जा रहे 10 गोवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने एंबुलेंस वाहन को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, सुबह बिसनूर जोड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुलताई रोड की ओर से एक एंबुलेंस आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा टॉर्च की रोशनी से रुकने का संकेत देने पर चालक वाहन को तेजी से भगाकर रगडगांव-गेहूंबारसा रोड की ओर ले गया और संजू काकोडिया के घर के पास एंबुलेंस छोडक़र खेतों की ओर भाग गया। पुलिस ने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एमएच -06, जे -9255 नोट किया। एंबुलेंस का पिछला गेट खोलने पर अंदर 10 गोवंश मुंह और पैर बंधे हुए अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर भरे मिले। प्रारंभिक जांच में गोवंश को महाराष्ट्र की ओर वध के लिए ले जाने की पुष्टि हुई। मौके पर गवाह पवन कवडकर एवं संजू काकोडिया की मौजूदगी में एंबुलेंस वाहन एवं 10 गोवंश (कुल अनुमानित कीमत करीब 4 लाख 78 हजार रुपये) को 19 नवंबर 2025 को शाम 5.30 बजे जब्त किया गया।

100 फीसदी डिजिटाइजेशन करने वाले बीएलओ को कलेक्टर श्री जैन ने किया सम्मानित

बैतूल। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जिले में मतदाताओं से प्राप्त गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन द्वारा सम्मानित किया गया। विधानसभा आमला के मतदान केंद्र 250 के बीएलओ शिक्षक दीपक वर्मा ने अपनी विधानसभा में सर्वप्रथम 100 फीसदी डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया। आमला के ही मतदान केंद्र 160 की बीएलओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती संगीता पवार ने भी शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसी तरह विधानसभा मुलताई में मतदान केंद्र 200 की बीएलओ शिक्षक श्रीमती सत्यभामा कवडक़र एवं मतदान केंद्र 201 की बीएलओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती मीना चढ़ोकार ने भी 100 फीसदी डिजिटाइजेशन कर अपनी विधानसभा का नाम अग्रणी सूची में दर्ज कराया है। कलेक्ट्रेट में प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन ने चारों बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में इस प्रकार की सक्रियता अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने आमला के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शैलेन्द्र बड़ोनिया और मुलताई के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजीव कहार के कार्यों की भी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद सहित निर्वाचन शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंडी प्रांगण की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर हुई बैठक

यातायात नियंत्रण, नीलामी प्रक्रिया, तौल व्यवस्था और सुरक्षा पर बनाए नए नियम

बैतूल। आगामी खरीफ सीजन के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भारसाधक अधिकारी डॉ.अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी के सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों सहित पुलिस थाना बैतूल बाजार के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडी परिसर में बढ़ते आवागमन, नीलामी व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। व्यापारियों ने सर्वसम्मति से कई आवश्यक सुधार प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी। एसडीएम डॉ.सिंह ने कृषकों द्वारा मक्का की उपज वाहन, ट्रॉली में खुले रूप में लाने पर प्राथमिकता के साथ सर्वप्रथम नीलामी कराई जाकर मंडी बड़े तौल कांटे पर वाहन संहित तुलवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रांगण में कृषि उपजों की नीलामी के क्रम में ही तुलाई कार्य प्रारंभ कराया जाए एवं तौल कार्य प्रारंभ होने पर ही संबंधित व्यापारियों द्वारा सफाई के लिए महिलाओं को प्रवेश दिया जाए, इसके पूर्व महिलाओं का प्रवेश पूर्णत- प्रतिबंधित रखा जाए। इसके अलावा प्रांगण के समस्त सीसीटीव्ही कैमरे यथा-स्थान एवं चालू स्थिति में हो, पुलिस विभाग से चर्चा कर रात्रि के समय पुलिस गश्त प्रारंभ कराई जाए एवं मंडी के बड़े तौल कांटे की दरें निर्धारित कराई जाए।

सांकेतिक ध्वनि देने के पश्चात नीलामी होगी प्रारंभ- मंडी प्रांगण में आने वाली कृषि उपजों में सर्वप्रथम सोयाबीन की नीलामी प्रातः 09.30 बजे सांकेतिक ध्वनि देने के पश्चात नीलामी प्रारंभ होगी। तत्पश्चात मक्का के लिए प्रातः 10.30 बजे से नीलामी प्रारंभ होगी। इसी क्रम में गेहूं प्रातः 11.30 बजे एवं शेष समस्त गल्ला की नीलामी का समय 12:30 बजे निर्धारित किया गया है। उपरोक्त निर्धारित समय पर सांकेतिक ध्वनि, घंटा ध्वनि देने के ठीक 5 मिनट पश्चात 2 या 3 व्यापारियों की उपस्थिति में संबंधित उपजों का नीलामी प्रांगण प्रभारी एवं सहायक कर्मचारियों द्वारा आवश्यक रूप से प्रारम्भ कराई जाएगी एवं कृषि उपजों की नीलामी के मध्य दोपहर 01.30 बजे से 02.30 बजे तक का समय व्यापारियों एवं कर्मचारियों के लिए भोजन अवकाश के लिए निर्धारित किया गया है। प्रांगण में प्रतिदिन कृषि उपजों की नीलामी के लिए अंतिम समय सायं 5 बजे निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक ढेरियों पर नीलामी बोली लगाई जाएगी– प्रांगण में प्रतिदिन कृषि उपजों के वाहनों का आगमन प्रातः 10 बजे से आगामी दिवस के प्रात- 5 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रांगण में किसानों द्वारा लगाई गई उपजों की प्रत्येक ढेरियों पर नीलामी बोली लगाई जाएगी एवं मंडी द्वारा निर्धारित उपजों के लिए आरक्षित शेड, स्थानों पर कृषि उपज नहीं डाले जाने पर उस उपज की ढेरी पर नीलामी बोली नहीं लगाई जाएगी। कृषकों की उपजों के तौल के लिए मंडी प्रांगण में चल रहे समस्त तौल कांटो की रेण्डमली जांच मंडी द्वारा की जाएगी एवं तौल समाप्ति पर मंडी के कांटे मंडी में जमा होंगे तथा दूसरे कार्य दिवस तुलैया को जारी किए जाएगे। मंडी द्वारा निर्धारित उपजों के लिए आरक्षित शेड, स्थानों पर कृषि उपज नहीं डाले जाने पर उस उपज की ढेरी पर नीलामी बोली नहीं लगाई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव हैदराबाद में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे

22 नवंबर को हैदराबाद में होगा इंटरएक्टिव सेशन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 22 नवंबर को द लीला, हैदराबाद में आयोजित मध्यप्रदेश के उच्च स्तरीय इंटरएक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। सत्र में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, नीतिगत सुधारों और निवेश-अनुकूल माहौल जानकारी निवेशकों के साथ साझा की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योग प्रतिनिधियों को प्रदेश में विकसित औद्योगिक पार्कों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन, कनेक्टिविटी और निवेश प्रक्रियाओं की सहजता से अवगत कराएंगे। यह सत्र उद्योगों और निवेशकों को प्रदेश की वास्तविक औद्योगिक क्षमताओं के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करेगा।

हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, वैश्विक क्षमता केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं निर्माण, अभियांत्रिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का प्रमुख केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र के उद्योगपतियों से संवाद के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर प्रत्यक्ष विचार-विमर्श होगा।

सत्र में मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। उद्योगपति प्रदेश के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों, आधुनिक अवसंरचना और विभिन्न सेक्टरों की वास्तविक संभावनाओं को समझ सकेंगे। चयनित उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री के साथ एक-से-एक बैठक का अवसर मिलेगा, जिससे वे निवेश या विस्तार से संबंधित प्रस्तावों पर सीधे चर्चा कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश सरकार उन कंपनियों के लिए सभी आवश्यक सुविधा, मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराएगी, जो प्रदेश में निवेश या विस्तार पर विचार कर रही हैं।

सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ, उद्योग-अनुकूल नीतियाँ और विकसित अवसंरचना मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख निवेश केन्द्रों में शामिल करती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हैदराबाद के उद्योगपतियों से यह इंटरएक्टिव सेशन महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर को देंगे बड़ी सौगात,39.80 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा विदिशा जिले की ग्राम पंचायत कागपुर में 21 नवम्बर को पंचायत क्षेत्र में 39.80 करोड रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इन विकास कार्यों से आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर के रहवासियों को और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के 34.05 करोड़ की लागत के 135 नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों एवं कागपुर (कनारी) से विदिशा-अशोकनगर मार्ग का भूमिपूजन और आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर में 5.75 करोड़ की लागत से बनाए गए हाट बाजार के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

हितलाभ का वितरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम स्थल पर विविध योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे। इसमें सीसीएल ऋण वितरण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मध्यकालीन पांच वर्षीय योजना अंतर्गत ऋण, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मैत्री योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कस्टम हायरिंग, कृषि अद्योसंरचना ऋण, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे।

सांची में 29 तथा 30 नवम्बर को महाबोधि महोत्सव एवं मेला का आयोजन

रायसेन (निप्र)। जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची में 29 तथा 30 नवम्बर 2025 को महाबोधि महोत्सव एवं मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा द्वारा मंगलवार को गेटवे रिट्रीट सांची में आयोजित बैठक में महाबोधि महोत्सव एवं मेला आयोजन की तैयारियों हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में महाबोधि सोसायटी के धर्मगुरू भी उपस्थित रहे। प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि सांची महोत्सव और मेले में प्रदेश ही नहीं देश और विदेश से भी पर्यटक आते हैं जिसके दृष्टिगत गरिमामय तथा व्यवस्थित आयोजन हेतु सभी तैयारियां समय से पहले ही पूरी कर ली जाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बेरिकेडिंग आदि के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के उपरांत प्रभारी कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा अधिकारियों के साथ बौद्ध स्तूप परिसर पहुंचकर भ्रमण किया गया तथा पार्किंग, पर्यटकों के स्तूप परिसर में आगमन-निर्गमन, स्वच्छता व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, एसडीएम श्री मनीष शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

जिले में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु वितरित की जा रही है फूड बॉस्केट

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले को कुपोषणमुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों द्वारा अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों आदि के सहयोग से कुपोषित बच्चों को फूड बॉस्केट वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पढ़रियाखुर्द, कोटपारगणेश, सुल्तानगंज, खरबई, बेगमगंज, गैरतगंज सहित अन्य ग्रामों तथा निकायों में कुपोषित बच्चों को फूड बॉस्केट वितरित की गई। साथ ही महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा कुपोषित बच्चों के माता-पिता से गृह भेंट कर बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण आहार का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही घर पर ही सुगमता से उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से पौष्टिक आहार बनाने की विधि बताई जा रही है।

सिविल सर्जन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। सिविल सर्जन डॉ. जगदीश घोरे ने मंगलवार को जिला अस्पताल की विभिन्न शाखाओं का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति सामने आई। पैथोलॉजी विभाग में जांच के समय लैब तकनीशियन श्रीमती नमिता मिश्रा और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रार्थना ताम्रकार ड्यूटी पर नहीं मिलीं। दोनों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात एमसीएच भवन का भी निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में सोनोग्राफी कक्ष में पहुंचने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रसूताओं की सोनोग्राफी करते हुए पाई गईं। वहीं एएनसी एवं पीएनसी वार्ड के निरीक्षण में महिला रोग विशेषज्ञ अनुपस्थित मिलीं, जिनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। एसएचआईवी शाखा में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदीप दरवाई अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिले, जिसके चलते उन्हें स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान आरएमओ डॉ. रानू वर्मा उपस्थित रहे। सिविल सर्जन ने सभी कर्मियों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कठपुतली और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के माध्यम से जन जागरूकता लाई जा रही है। तत्संबंध मेंमहिला एवं बाल विकास संचालनालय के निर्देशानुसार भोपाल के कलाकारों द्वारा कठपुतली और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं व बच्चों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु जिले की विविध परियोजनाओं में आयोजित किये जा रहे हैं।

कलेक्टर ने इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेन्ट मेनेजमेन्ट के विद्यार्थियों से की चर्चा

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को नोएडा के आईएसडीएम (इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेन्ट मेनेजमेंट के जिले के भ्रमण पर आए विद्यार्थियों से चर्चा की। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान कलेक्टर ने उनके जिज्ञासों का समाधान भी किया। उल्लेखनीय है कि आईएसडीएम नोएडा में अध्ययनरत 8 विद्यार्थी 9 से 21 नवम्बर तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर आए थे। इस दौरान इन विद्यार्थियों ने चिकलपाट, बांसपानी, चन्द्रखाल, कायदा, पिपल्या, जिनवानिया सहित जिले के अन्य ग्रामों का भ्रमण सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन किया।

कलेक्टर ने जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा की

हर-घर नल से जल योजना में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से संचालित हो - कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचे इसके लिए जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय की विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित 522 नल जल योजनाओं पर किए जा रहे कार्यों की वस्तु स्थिति की जानकारी ली।

बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में 522 नल जल योजनाओं में से 378 योजनाएं पूर्ण हुई है, पूर्ण योजनाओं में से 262 योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित भी की जा चुकी है। जहां जल प्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। 144 योजनाएं हस्तांतरित करने के लिए प्रगति रथ है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों और आंगनबाड़ियों में नल जल योजना के माध्यम से जलप्रदाय व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने समितियों को उपलब्ध कराई गई किट और पानी की टेस्टिंग इत्यादि के संबंध में भी निर्देश दिए हैं के अलावा उनारसी कला और गमाखर ग्राम में पानी टंकियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन की अघतन स्थिति, नल जल योजनाओं की भौतिक प्रगति की जानकारी, पूर्ण नल जल योजनाओं को हस्तांतरित किए जाने का विवरण, एफएचटीसी टारगेट, रिपोर्टेड एवं प्रमाणीकरण ग्रामों की जानकारी, प्रगतिरत एकल नल जल योजनाओं में किये जा रहे रोड रेस्टोरेशन की स्थिति, स्वीकृत टंकियां की स्थिति और विदिशा जिले में स्थापित हैंड पंपों के चालू और बंद की स्थिति सहित पीव्हीटीजी ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था की जानकारी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।

ऑनलाइन गणना प्रपत्र अपलोडिंग में बैतूल जिला अव्वल

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को मिली प्रशंसा

बैतूल (निप्र)। जिले में चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वेक्षण से भरे गए गणना प्रपत्रों को मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया पूरे वेग से जारी है। अभियान की प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षत जैन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ की प्रशंसा की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के कार्यों का दैनिक मूल्यांकन किया जा रहा है। मुलताई विधानसभा क्षेत्र 129 के मतदान केंद्र क्रमांक 194 के बीएलओ सुभाष गाढरे ने 98.66 प्रतिशत दर्जीकरण कर विधानसभा क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं आमला विधानसभा क्षेत्र 130 के मतदान केंद्र क्रमांक 160 की बीएलओ संगीता पवार ने 99.30 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर प्रथम स्थान हासिल किया। मतदान केंद्र 187 के बीएलओ सुनिता कवड़े ने 96.30 प्रतिशत दर्ज कर दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि आमला क्षेत्र के ही मतदान केंद्र क्रमांक 256 के बीएलओ दीपक वर्मा ने 94.60 प्रतिशत कार्य पूरा कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र 132 के मतदान केन्द्र क्रमांक 86 की बीएलओ सुश्री मेघना डाली ने 83.71 प्रतिशत एवं विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही के मतदान केन्द्र क्रमांक 230 की बीएलओ सुश्री सुभद्रा द्वारा 76.26 प्रतिशत तथा विधानसभा क्षेत्र 131-बैतूल के बीएलओ श्री दीपक राव द्वारा 48.21 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर अपनी विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्र के डिजिटाईजेशन कार्य में प्रथम स्थान पर है। कलेक्टर श्री अक्षत जैन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाकी बीएलओ भी प्रेरणा लेते हुए निर्धारित समयावधि में अपने कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

छात्रावास अधीक्षिका निलंबित

विदिशा (निप्र)। जनजातीय गौरव दिवस पर बासौदा के मानस भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शासकीय समुदाय कल्याण केन्द्र बरेठ के छात्रों को मानस भवन तक लाने ले जाने के कार्यों में लापरवाही बरतने पर अधीक्षिका श्रीमती मनीषा शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक द्वारा जारी किया गया है। जिला संयोजक श्री सुनील मरकाम के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षक प्रभारी अधीक्षिका सामुदायिक कल्याण केन्द्र बरेठ श्रीमती मनीषा शर्मा को निलंबन काल अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग विदिशा नियत किया गया है।

सिकल सेल गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर एएनसी प्रशिक्षण आयोजित

10 ब्लॉकों के चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग ऑफीसरों को दिया प्रशिक्षण

बैतूल (निप्र)। एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी बैतूल में मंगलवार को जिले में सुरक्षित मातृत्व को सुदृढ़ बनाने तथा सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित गर्भवती महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष प्रसवपूर्व देखभाल एएनसी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के सभी 10 विकासखंडों के चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग ऑफीसर, लेब टेक्नीशियन ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को सिकल सेल प्रभावित गर्भवती महिलाओं में संभावित जटिलताओं की समय पर पहचान, निर्धारित एएनसी प्रोटोकॉल के प्रभावी पालन, सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षित करना था। सीएमएचओ डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने कहा कि बैतूल जिला सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित देखभाल जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सिकल सेल, गर्भवती माता के साथ-साथ आने वाले बच्चे के लिये भी गंभीर समस्या है। गर्भवती महिला सिकल सेल होने पर, समय पूर्व प्रसव, गुर्दे एवं यकृत से संबंधित रोग, कम वजन बढ़ना, रक्त के थक्के बनने की समस्या, मूत्र मार्ग एवं स्वसन तंत्र का संक्रमण इत्यादि एवं होने वाले शिशु को भ्रूण की वृद्धि में रूकावट, जन्म के समय कम वजन, मृत जन्म इत्यादि जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। शासन का मिशन है सिकल सेल बीमारी का वर्ष 2047 तक उन्मूलन किया जाना है, हम इस लक्ष्य को इससे पूर्व प्राप्त करने के भरपूर प्रयास करेंगे। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.जगदीश घोरे ने बताया कि सिकल सेल कार्यक्रम के अंतर्गत स्क्रीनिंग के बाद उसकी पुष्टि करना, मरीज को उपचार देना एवं उसका फॉलोअप करना बहुत आवश्यक है, साथ ही जो दवाईयां चल रही हैं उसकी पोर्टल पर एन्ट्री करना आवश्ययक है। प्रशिक्षण का मुख्य तकनीकी सत्र जिला सिकल सेल कार्यक्रम की नोडल अधिकारी एवं पैथोलॉजिस्ट डॉ. अंकिता सिते द्वारा संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान गंभीर एनीमिया, संक्रमण, दर्द संकट (क्राइसिस), समयपूर्व प्रसव तथा मातृ एवं शिशु जटिलताओं का जोखिम अधिक रहता है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रारंभिक पंजीयन कर उन्हें उच्च जोखिम श्रेणी में दर्ज करना अनिवार्य है, साथ ही नियमित सीबीसी आवश्यक प्रयोगशाला जाँच, सतर्क निगरानी, पोषण परामर्श तथा आवश्यकता पड़ने पर समय पर एफआरयू या जिला अस्पताल में रेफरल जीवनरक्षक सिद्ध हो सकता है। प्रशिक्षण में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ भावना कवडकर ने बताया कि प्रसव प्रबंधन, रेफरल प्रोटोकॉल, प्रसव के दौरान आवश्यक सावधानियाँ तथा प्रसवोत्तर संक्रमण नियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी।

कलेक्टर ने लंबित आवेदनो की समीक्षा की, आवेदनों का संतुष्टि से निराकरण पर दिया जोर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनो की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित इस बैठक में उन्होंने विभिन्न स्तरो पर प्राप्त आवेदनो के निराकरण के संबंध में विशेष पहल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन तहत लंबित शिकायत का संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराएं ताकि जिले की ग्रेडिंग रैंकिंग में सुधार परिलक्षित हो। 50 दिवस और 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की भी गहन समीक्षा की गई है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन, वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त आवेदनो के साथ-साथ समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में सम्मिलित विषयों पर आधारित आवेदनो के निराकरणो की अद्यतन जानकारियां प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि एल वन स्तर पर हीं आवेदन का निराकरण हो इसके लिए विभाग के जिलाधिकारियों को विशेष पहल करनी होगी।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागो के माध्यम से क्रियान्वित हितग्राहीमूलक योजनाओं व विशेष अभियान के तहत संपादित किए गए कार्यों की भी समीक्षा की। लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएमयू, उपार्जन कार्य, नलजल योजनाएं, खाद एवं बीज की आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण, जल मिशन के कार्य, स्वास्थ्य विभाग के कार्य व आयुष्मान पखवाडा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की स्थिति, खनिज, परिवहन, आबकारी एवं पंजीयन विभाग की राजस्व प्राप्ति और उनके साप्ताहिक निरीक्षण कार्यों की जानकारियां प्राप्त की गई हैं। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में पीएचई विभाग की नल-जल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें, इसके अलावा उन्होंने विशेष कर विदिशा और कुरवाई क्षेत्र में नरवाई जलाने के प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई के साथ-सा अवेयरनेस लाने हेतु जन जागरूकता व प्रचार प्रसार के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है।

स्वास्थ्य सेवाएं जनता का अधिकार हैं और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : कलेक्टर

- स्वास्थ्य सेवाओं में सुस्ती पर कलेक्टर सख्त, कई अधिकारियों को नोटिस के निर्देश
- जिला स्वास्थ्य समिति बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. का कड़ा रुख, सुधार के दिए सख्त निर्देश

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण पुनर्वास केंद्रों की कार्यप्रणाली, टीकाकरण प्रगति, एनआरसी एवं एसएनसीयू की स्थिति, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा दवाई उपलब्धता सहित संपूर्ण गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलने पर गहरी नाराज़गी जताई और कई अधिकारियों को संतोषजनक प्रगति न होने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है, वहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएँ और आगामी समीक्षा में ठोस सुधार दिखना चाहिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य संस्थान दवाओं की उपलब्धता, लेब जांच की नियमितता, मातृ एवं बाल मृत्यु समीक्षा की समयबद्ध रिपोर्टिंग, टीकाकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति तथा एनसीडी स्क्रीनिंग में हर पात्र नागरिक की जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 'स्वास्थ्य सेवाएँ जनता का मूल अधिकार हैं और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हर ब्लॉक में अधिकारी स्वयं फील्ड विज़िट करें और वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।' उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में स्वच्छता, रोगी सुविधा, रिकॉर्ड प्रबंधन और एनक्यूएएस मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा जिन संस्थानों का प्रदर्शन लगातार कमजोर है, वहाँ विशेष समीक्षा की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आगामी समीक्षा में ठोस परिणाम प्रस्तुत करने, सभी लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने और सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बैठक में प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएमएचओ डॉ सुधीर कुमार डेहरिया, डीपीओ श्री ज्ञानेश खरे सहित सभी स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे।

राइट क्लिक

बिहार चुनाव में हार से महागठबंधन ने क्या सीखा ?

अजय बोकिल

जैसा कि इस ब्लॉग में पहले लिखा गया था कि बिहार में सरकार चाहे किसी की भी बनें, नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं, सत्य साबित हुआ है। हालांकि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, महागठबंधन की दयनीय पराजय और नीतीश कुमार के दसवीं बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बनने के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, उनमें पहला तो नीतीश कब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और दूसरा इस हार के बाद महागठबंधन के मुख्य घटक दलों ने कोई सबक लिया है या नहीं या फिर वो अभी भी 'मेरे मुर्गे की डेढ़ टांग' वाली राजनीति पर आमादा हैं?

जहां तक नीतीश कुमार के सीएम पद पर टिकने की बात है तो बतौर मुख्यमंत्री उनकी यह आखिरी पारी होगी। लेकिन वो इस पद से कब हटेंगे अथवा हटाए जाएंगे, यह आगे की परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि नीतीश का अपना पक्का और प्रतिबद्ध वोट बैंक है। ऐसे में नीतीश तभी हटेंगे, जब वो खुद ऐसा चाहें अथवा कोई ऐसे अप्रत्याशित हालात बनें। उनके हटने से पहले भी बीजेपी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि नीतीश कुमार और जद यू के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उसके पाले में शिफ्ट हो जाए। राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान यह कहते रहे हैं कि बीजेपी जद यू के टुकड़े करा देगी। यह भविष्य में संभव है, लेकिन सहजता से होगा। बीजेपी नीतीश के विकल्प के तौर पर अति पिछड़े वर्ग के नेता सम्राट चौधरी को तैयार कर रही है।

नीतीश का क्या होगा, इससे भी अहम सवाल यह है कि इस हार से विपक्षी दलों ने क्या सीखा ? महागठबंधन के दो मुख्य घटकों राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस ने पराजय का तात्कालिक विश्लेषण कर अपनी सुविधा से हार के कारण खोज लिए हैं। जो हुआ, उसमे आत्ममंथन और सच को स्वीकार करने से ज्यादा ठीकरा फोड़ने किसी सिर की तलाश ज्यादा है। जहां तक राजद का प्रश्न है तो वहां हार के कारणों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा से ज्यादा जल्दी तेजस्वी यादव की विधायक दल नेता पर ताजपोशी की। इसके पीछे शायद यह डर था कि कहीं बीजेपी राजद में ही सेंध न लगा दे। यही कारण है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी अपने परिवार के भीतर लगी आग की परवाह न कर बेटे तेजस्वी को विधायक दल का नेता बनवाने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी बैठक से चले गए। इस बीच पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने राबड़ी के आवास के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। दरअसल राजद की इस करारी हार का कारण तेजस्वी के दो सलाहकारों संजय यादव और रमीज नेमत को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन लालू परिवार उन्हें बचा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संजय यादव की रणनीति और चुनाव प्रबंधन की कमजोरी के कारण ही पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस चुनाव ने यह भी साबित किया कि राजद का एमवाय समीकरण अब पहले जैसा असरदार नहीं रह गया है। यादवों का एक तबका एनडीए की तरफ चला गया तो तेजस्वी द्वारा एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन औवेसी को 'एक्स्ट्रीमिस्ट' कहना मुसलमानों को नागवार गुजरा। राजद की समीक्षा बैठक में यह माना गया कि पार्टी लोगों तक अपनी बातों को सही ढंग से पहुंचाने में असफल रही। राजद नेता संजय कुमार ने कहा कि समीक्षा में इस बात पर चर्चा हुई कि है कि गलती कहां हुई, संगठन कहां कमजोर पड़ा, बूथ प्रबंधन ढीला रहा या फिर चुनावी संदेश जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा। अब पार्टी इसे सुधारने क्या कदम उठाती है, यह देखने की बात है।

उधर कांग्रेस द्वारा हार की फौरी समीक्षा में अपनी कमजोरियों को सुधारने की जगह एसआईआर और चुनाव आयोग को दोषी पाया गया। पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग तुरंत यह दिखाना चाहिए कि वह भाजपा की 'छाया' में काम नहीं कर रहा है। एसआईआर का जो मुद्दा बिहार में पिट चुका, उसे पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने जा रही है। अभी 12 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम मतदाता सूची अगले साल 7 फरवरी को आएगी। उसके पहले कांग्रेस दिसम्बर के पहले हफ्ते में दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की रैली करने जा रही है। इससे क्या लाभ होगा, समझना मुश्किल है। दरअसल पार्टी की समस्या ऐसे मुद्दों की तलाश है, जो जनता से सीधे कनेक्ट करे। चौकीदार चोर, जाति जनगणना, संविधान बचाओ, मोदी को आइडियालॉजिकली उड़ा देने और वोट चोरी के बाद अब एसआईआर का मुद्दा भी पिट गया है। दूसरे, चुनाव सिर्फ 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने से नहीं जीते जाते। उसके लिए ऐसी ड्रिलिंग मशीनों की जरूरत होती है, जो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पैठ बना सके। यूं कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस भी भाजपा की तरह वोटरों से सीधे कनेक्ट, बूथ मैनेजमेंट आदि पर ध्यान देगी ताकि अपने वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाए जा सके। हालांकि जमीन पर वैसा ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। हालांकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया कि पार्टी ने मतदाता सूचियों की अखंडता की सुरक्षा के लिए 'एक व्यापक रणनीति समीक्षा' की है। ऐसे समय में जब संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कमज़ोर है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण 'बहुत ही निराशाजनक' रहा है।

प्रश्न यह भी है कि महागठबंधन की हार के लिए राजद और कांग्रेस में ज्यादा जिम्मेदार कौन है? या फिर दोनों हैं? चुनाव के दौरान दोनों में मनमुटाव के अलावा यह पराजय गठबंधन की आंतरिक कलह, रणनीतिक चूक और बाहरी हमलों का नतीजा मानी जा रही है। तेजस्वी को चुनाव प्रबंधन से ज्यादा चिंता जल्द से जल्द सीएम पद की शपथ लेने की थी। जमीन के नीचे वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी हवा न तो तेजस्वी को थी और न ही राहुल गांधी को। बिहार से राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी में सभी तो टिकट बंटवारे और खुद चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। निगरानी करने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चुनाव का कोई प्रबंधन ही नहीं है। बिहार के लोगों का मानना है कि राहुल और तेजस्वी दोनों एकजुट ताकत बनने के बजाए एक दूसरे की नाव डुबो गए।

इस बीच देश की 272 जानी-मानी हस्तियों ने एक खुला पत्र जारी कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष हमला करते हुए उनके रवैये की आलोचना की है। सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक के तौर पर उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं, बल्कि उसकी आधारभूत संस्थाओं के खिलाफ़ ज़हरीली बयानबाज़ी से हमला हो रहा है। कुछ राजनेता, नीतिगत विकल्प पेश करने के बजाय, अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। वैसे यह पत्र भी उसी तरह से प्रायोजित हो सकता है, जैसा कि प्रबुद्ध लोगों का एक खेमा अक्सर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना और जनता को भाजपा से कथित रूप से सावधान करने के लिए जारी करता रहता है।

दिलचस्प बात तो यह है कि बिहार में महागठबंधन की तगड़ी हार का पराजित पार्टियों से ज्यादा गंभीर विश्लेषण तो पाकिस्तान में हुआ है। वहां के विश्लेषकों ने टीवी डिबेट्स में कहा कि इस चुनाव में जहां कांग्रेस ने 'लोकतंत्र' जैसे वैचारिक मुद्दों को उठाया, वहीं बीजेपी ने कुशलता से आम नागरिक के जीवन से जुड़े व्यावहारिक विषयों जैसे- रोटी, पानी और आर्थिक सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। 'विकास-केंद्रित' रणनीति ने ही एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई। इन विश्लेषकों ने पाक सरकार को भी इसी 'जन-केंद्रित' मॉडल को अपनाने की सलाह दी है।

वैसे इन नतीजों के बाद महागठबंधन के नेतृत्व को बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आगे-आगे देखिए, होता है क्या?

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

कार-ट्रक की टक्कर में 3 वेटनरी डॉक्टर्स की मौत,4 घायल

गुना में दोस्त की शादी समारोह से लौट रहे थे

गुना (नप्र)। गुना के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के भिलेरा गांव के पास बुधवार रात करीब 2 बजे तेज कार और ट्रक की टक्कर में 3 युवा वेटनरी डॉक्टर्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक अपने दोस्त की

शादी से लौट रहे थे। दो घायलों को हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर किया गया है। बाकी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, कार गुना की तरफ से आ रहे लगभग 12-पहिया ट्रक से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। टक्कर से ट्रक भी नियंत्रण खोकर सड़क पर घूम गया और पलट गया।

मृतकों और घायलों की पहचान हुई

हादसे में भिंड के आकाश चौरसिया, श्योपुर के नमोनारायण मीना और गुना के चांचौड़ा के मनीष कुमार जाटव की मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल योगेश करोलिया और पारस करोलिया को भोपाल रेफर किया गया है। जबकि सूरज जाटव और अजय शाक्य का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सभी दोस्त वेटनरी प्रेक्टिसिंग डॉक्टर

सभी युवक वेटनरी के प्रेक्टिसिंग डॉक्टर थे और इन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। बुधवार रात वे सभी अपने एक साथी की शादी समारोह में शामिल होने गुना जिले के आरोन पहुंचे थे और वहीं से वापस लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

घायल देर तक सड़क पर पड़े रहे, राहगीर ने दी सूचना

रात का समय होने के कारण सड़क पर आवाजाही नहीं थी। हादसे में घायल युवक काफी देर तक सड़क पर पड़े कराहते रहे। बाद में एक राहगीर वहां से निकला, जिसने मौके का हाल देखकर तुरंत डायल-112 पर कॉल किया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची। कार बुरी तरह दब जाने के कारण टीम को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। सभी घायलों और मृतकों को कार के मलबे से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया।

कूनो में चीता 'मुखी' ने 5 शावकों को दिया जन्म

सीएम मोहन यादव ने दी बधाई, भारत में पहला सफल प्रजनन, प्रोजेक्ट चीता को मिली सफलता

श्योपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारतीय मूल की मादा चीता 'मुखी' ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि भारत के चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। मां और शावक पूरी तरह स्वस्थ बताए गए हैं।

यह पहली बार है जब भारत में जन्मी किसी मादा चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। लगभग 33 महीने की मुखी अब 'प्रोजेक्ट चीता' की पहली ऐसी मादा बन गई है, जिसने पांच शावकों को जन्म देकर संरक्षण प्रयासों की सफलता को मजबूती दी है।

कूनो में चीता प्रजनन सफल, सीएम ने टीम को बधाई दी

विशेषज्ञों के अनुसार, यह सफल प्रजनन इस बात का महत्वपूर्ण संकेत है कि चीते भारतीय आवासों में तेजी से अनुकूल हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य और व्यवहार प्राकृतिक परिस्थितियों में संतोषजनक पाया गया है।

यह उपलब्धि भारत में एक आत्मनिर्भर, स्थिर और आनुवंशिक रूप से विविध चीता जनसंख्या स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे देश के दीर्घकालिक संरक्षण लक्ष्यों को बल मिलेगा और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी मादा चीता मुखी द्वारा पाँच शावकों को जन्म देने पर प्रसन्नता व्यक्त कर बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि माँ और शावक स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि भारत में चीता पुनरुत्पादन पहल के लिए यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। तैतीस माह की उम्र में मादा चीता 'मुखी' अब शावकों को जन्म देने वाली भारत में जन्मी पहली मादा चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारतीय आवासों में चीता प्रजाति के अनुकूलन, स्वास्थ्य और दीर्घकालिक संभावनाओं का एक मजबूत संकेतक है। यह उपलब्धि भारत में आत्मनिर्भर और आनुवंशिक रूप से विविध चीता आबादी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में जैव विविधता के संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हो रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस खबर को सोशल मीडिया के जरिए से साझा किया। उन्होंने कूनो की टीम और वन विभाग को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी।

भारत में 32 तो कूनो नेशनल पार्क में चीता की संख्या 29 हुई

वर्तमान में, भारत में चीतों की कुल संख्या 32 हो गई है, जिसमें से 29 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में और 3 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखे गए हैं। यह संख्या चीता पुनर्वास परियोजना की स्थिरता को प्रदर्शित करती है। नामीबियाई मादा चीता 'ज्वाला' (सियाया) की संतान 'मुखी' (जिसे ज्वाला की बेटी होने के कारण मुखी नाम दिया गया) का सफल प्रजनन इस उपलब्धि का केंद्र है। मुखी द्वारा पांच शावकों को जन्म देना न केवल संख्या बढ़ाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि भारत में जन्मी चीता यहां के पर्यावरण में सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकती है। यह उपलब्धि भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो देश में चीता के दीर्घकालिक भविष्य के लिए आशा जगाती है।

यह तीसरी पीढ़ी यहां के मौसम के प्रति ज्यादा अनुकूलन करेगी

'मुखी' (ज्वाला की संतान) द्वारा पाँच शावकों को जन्म देना 'प्रोजेक्ट चीता' के लिए एक अभूतपूर्व पीढ़ीगत छलांग है। यदि ज्वाला को पहली पीढ़ी (आयातित) मानें, तो मुखी दूसरी पीढ़ी है, और मुखी के शावक तीसरी पीढ़ी हैं। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों के अनुसार, ये तीसरी पीढ़ी के शावक भारत की धरती पर पैदा हुई मां मुखी की संतान है, जो इन्हें भारतीय वातावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करेगी, क्योंकि वह जन्म के साथ यहां के मौसम से अनुकूलन कर रही है। इनका प्राकृतिक रूप से यहाँ जन्म लेना, चीता प्रोजेक्ट की बढ़ी सफलता है।

डिजिटल डिग्री वेरीफिकेशन विद्यार्थी हित की सार्थक पहल : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल द्वारा बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय का डिजिटल डिग्री वेरीफिकेशन पोर्टल का शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि डिजिटल डिग्री वेरीफिकेशन पोर्टल उच्च शिक्षा की बेहतरी की दिशा में ऐतिहासिक क़दम है। पोर्टल, विद्यार्थी हित की सार्थक पहल है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों में तकनीकी नवाचार से विद्यार्थियों को वेरीफिकेशन की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी। रोज़गार और प्लेसमेंट आदि ज़रूरी प्रक्रियाएं सुरक्षित रूप में सरलता और शीघ्रता से हो सकेगी।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष नवाचार सराहनीय है। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से डिग्री वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया को समझा। स्वयं रेंडम परीक्षण किया। पोर्टल को सफलतापूर्वक लोकार्पित करने के लिए समस्त विश्वविद्यालय प्रबंधन को बधाई दी। राज्यपाल श्री पटेल ने गुरुवार को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के डिजिटल डिग्री वेरीफिकेशन पोर्टल का वन क्लिक से शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया था।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, विश्वविद्यालय के कुलगुरू श्री सुरेश कुमार जैन, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, कुल सचिव श्री अनिल शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हेलिकॉप्टर से पहुंचें कान्हा, बांधवगढ़-सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

एमपी में पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा शुरु, पहले दिन ट्रायल, कल से आम व्यक्ति के लिए उड़ेंगे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत आज, गुरुवार से हो गई है। टूरिस्ट 3 टाइगर रिजर्व- कान्हा, बांधवगढ़-एसटीआर (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) के साथ ईको टूरिज्म सेक्टर और स्पिरिचुअल सेक्टर में हेलिकॉप्टर से जा सकेंगे। सप्ताह में 5 दिन तक उड़ान रहेंगी। बुधवार और गुरुवार को उड़ान नहीं है। इसलिए आज ट्रायल हो रहा है। इस दिन मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि हेलिकॉप्टर में बैठे, जबकि कल, शुक्रवार से हेलिकॉप्टर आम लोगों के उड़ेंगे।

1 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा की औपचारिक शुरुआत कर दी थी, लेकिन नियमित उड़ानें 20 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस कार्यक्रम में 20 नवंबर से हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन शेड्यूल में आज का दिन शामिल नहीं है। इसलिए आम व्यक्तियों के लिए बुकिंग नहीं की गई है।

डबल इंजन वाले हेलिकॉप्टर- नई हेलिकॉप्टर सेवा में शामिल सभी हेलिकॉप्टर डबल इंजन वाले हैं। ताकि, उसमें बैठे यात्री सुरक्षित रह सके। सुरक्षा के पैमाने जानने के लिए जनप्रतिनिधियों को पहले भोपाल से पचमढ़ी, मढ़ई के लिए सांसद दर्शनसिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, विजय पाल सिंह आदि ने सफर किया। बकायदा, इनका वजन कितना है? यह भी जांचा गया। ताकि, हेलिकॉप्टर में ज्यादा वजन न हो। छोटे-छोटे रूट्स बनाए गए हैं। ताकि इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा हो। यही बैकअप स्थान चिन्हित किए गए हैं।

जबलपुर में मंत्री ने किया सफर- एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में पीएमश्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट से लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सुबह 11.20 बजे इस सेवा का शुभारंभ

किया। अब जबलपुर से कान्हा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, धार्मिक स्थल मैहर, चित्रकूट और अमरकंटक पहुंचना आसार होगा। यह सेवा सप्ताह में पांच दिन रहेगी। केंद्रीय विमानन मंत्रालय और मप्र पर्यटन बोर्ड की देखरेख में फ्लाई ओला कंपनी इसका संचालन करेगी। जबलपुर से सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पर्यटक उड़ान भर सकेंगे।

टूरिस्ट हब है महाकौशल- इस मौके पर मंत्री सिंह ने कहा कि महाकौशल टूरिस्ट हब है। जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हवाई सेवा के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिल गई है। बहुत ऐसे पर्यटक आते हैं, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर घूमना चाहते हैं, लेकिन सड़क मार्ग से यह मुमकिन न था।

पीएमश्री हेलिकॉप्टर सेवा ने इस समस्या को खत्म कर दिया है। इससे जहां कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थानों तक पहुंचना आसान हो गया है, वहीं रोजगार भी बढ़ेगा। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि भेड़ाघाट के पास हेलीकॉप्टर का बेस बनाया है। जहां से पर्यटकों को उनके पसंद के पर्यटन स्थल ले जाया जाएगा।

इस सेवा के लिए अलग-अलग दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया है। जबलपुर से सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पर्यटक उड़ान भर सकेंगे। सभी पर्यटन स्थलों में कंपनी ने हैलीकॉप्टर की सफल लैडिंग के लिए बेस बनाया है। पर्यटकों को पर्यटन स्थल के आसपास उतारने की व्यवस्था है। पर्यटक कंपनी के ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी ले सकते हैं।

इंदौर में 6 विशेष अतिथियों को लेकर उड़ा हेलिकॉप्टर- इंदौर से भी पीएमश्री हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन इंदौर से उज्जैन के लिए 6 विशेष अतिथियों ने उड़ान भरी है। पर्यटन विभाग के अनुसार, इंदौर से उज्जैन का किराया 5 हजार, उज्जैन से ओंकारेश्वर का साढ़े 6 हजार और ओंकारेश्वर से इंदौर का किराया 5 हजार 500 रूपए होगा।

नया व्यापार सृजित करने वाले कर्मचारी को इंसेंटिव देने की योजना जल्द : मंत्री श्री सारंग

डिफॉल्टर किसानों के लिये भी योजना होगी शुरू

भोपाल (नप्र)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि पैक्स में नया व्यापार सृजित करने वाले कर्मचारी को इंसेंटिव देने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही डिफॉल्टर किसानों के लिये भी योजना लाई जा रही है। इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि सोसायटी में कुछ गडबड़ी पर भी किसानों पर असर नहीं हो। यह बात मंत्री श्री सारंग ने अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आयोजित 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन समारोह में कही। समारोह में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने विषयक पर चर्चा की गई। मंत्री श्री सारंग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी बैंकों और पैक्स को सम्मानित किया। उन्होंने अपेक्स बैंक में ई-ऑफिस तथा सहकार-सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया।

कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी पारदर्शी- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी आंदोलन के हर आयाम को मजबूती के साथ स्थापित कर रही है। कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का काम कर रही है। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के माध्यम से सहकारी आंदोलन मजबूत होगा और सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी के माध्यम से हर पैक्स को कॉरपोरेट के साथ जोड़कर नये आयाम स्थापित किये जा रहे है। इससे पैक्स के साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा। पैक्स को फायदे के साथ कर्मचारी को भी लाभ दिलवाने का काम किया जायेगा।

सहकारिता विभाग की प्रत्येक पहल प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिये- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन तथा केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि मिशन से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश का सहकारिता विभाग सतत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से लेकर सीपीपीपी तक सहकारिता विभाग की प्रत्येक पहल प्रदेश के किसानों की खुशहाली तथा ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सहकारिता को जमीनी स्तर पर पहुँचना ही उद्देश्य- सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प ने कहा कि यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। अब यह अंतिम पडाव पर है। इसका उद्देश्य सहकारिता को जमीनी स्तर पर पहुँचना है। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया।